● वर्ष-4
● अंक-15
रायपुर, मंगलवार
27 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› सोलह कलाओं के अवतार...

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया एलान,

राज्य में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे विस चुनाव

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) का गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने एलान करते हुए कहा कि- उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले दोनों पार्टियों ने हालिया लोकसभा चुनाव में राज्य में एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने आठ और आजसू ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। राज्य में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस और राजद गठबंधन के तहत सत्ता में काबिज हैं।

शाह से मुलाकात के बाद किया एलान

बता दें कि आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इसका एलान किया है। सुदेश महतो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस अवसर पर झारखंड के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। एनडीए सरकार झारखंड राज्य के लिए आवश्यक है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।

चंपई सोरेन एनडीए का हिस्सा बने तो अच्छा होगा- सुदेश

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात और राज्य सरकार ने राज्य को जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, उस पर चर्चा हुई। यह तय हुआ है कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर पूछ गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो यह अच्छा होगा।

दुष्यंत चौटाला को भाजपा से तौबा, कांग्रेस का हाथ थामने की उम्मीद, विस चुनाव से पहले खोले पत्ते

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की थी। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे चुनावी माहौल में पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीच दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की थी। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे चुनावी माहौल में पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीच जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं आपको लिखकर ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जब चौटाला से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बारे पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो इसे संकट के तौर पर नहीं लेते। उनका मानना है कि जो होना लिखा था वह हो गया। अब मैं इसे एक मौके के तौर पर लेता हूं। हमारी पार्टी पिछली बार भी किंगमेकर थी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जेजेपी हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा अहम पार्टी होगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में जेजेपी एक भी सीट पर विजय हासिल नहीं कर पाई और 0.87 प्रतिशत वोट शेयर ही पार्टी को मिला। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जो भी भ्रष्टाचार है वो सब हुड्डा की वजह से है। दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि आज जो उपनिवेशीकरण हो रहा है उसके लिए हमें हुड्डा को धन्यवाद करना चाहिए।

जहां एक तरफ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर तंज किया। वहीं जब उनसे 'इंडिया' गठबंधन को लेकर सवाल किया गया कि क्या वो 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने जवाब में कहा कि देखते हैं अगर हमारे पास नंबर हुआ तो जरूर और अगर हमारी पार्टी को सही दर्जा दिया जाता है तो क्यों नहीं करेंगे।

मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन से की बात

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बातचीत के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि उनके और बाइडन के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा सबसे अहम रहीं।

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

पीएम मोदी ने बताया- हमारे बीच यूक्रेन समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन में शांति और स्थायित्व के लौटने के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और देश में सामान्य स्थिति के लौटने और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर नहीं रुक रहा है। इतना ही नहीं सरकारी महकमों, विश्वविद्यालयों और प्रमुख संस्थानों से हिंदु कर्मचारियों को हटाए जाने की भी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत के कई शहरों में जहां प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। वहीं अमेरिका के कई शहरों में हिंदु समुदाय इस मामले को लेकर अमेरिका सरकार पर दबाव बनाने में जुटा है।

हाल ही में यूक्रेन दौरे पर थे पीएम मोदी

इससे पहले पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में थे। इस दौरान उन्होंने न केवल राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय बातचीत की थी, बल्कि यूक्रेन की धरती से इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीति और बातचीत के उपायों की खुलकर वकालत की थी। इतना ही नहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि अगर भारत यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी करता है तो वो आने को लिए तैयार हैं।

यूक्रेन के हालात पर भारत और अमेरिका के नेताओं की यह बात ऐसे वक्त हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज होती नजर आ रही है। ध्यान रहे कि पीएम मोदी ने भारत की तरफ से इस युद्ध को खत्म करवाने में हर संभव मदद का भी भरोसा दिया।

ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री से भी हुई बात

प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां क्वाड कुनबे के सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात की तो वहीं उनकी बात क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से भी हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और बहुराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के लेकर बात की।

अब 21 दिन में होगा जन शिकायत का निवारण

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण की समयसीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिन थी। वहीं नए निर्देश के अनुसार जिन मामलों में शिकायत निवारण में अधिक समय लगने की संभावना है, वहां नागरिकों को अंतरिम जवाब दिया जाएगा।

शिकायतों को नहीं लौटा सकेंगे मंत्रालय-विभाग- सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मंत्रालयों-विभागों में लोक शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो

आपकी शिकायतों को नहीं लौटा सकेंगे मंत्रालय-विभाग

शिकायतों का शीघ्र, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान करेंगे। वहीं शिकायतों का बोझ अधिक होने वाले मंत्रालयों-विभागों में समर्पित नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी मामले में शिकायत को इस मंत्रालय-विभाग-कार्यालय से संबंधित नहीं है या इसके समकक्ष भाषा में बताकर बंद नहीं किया जाएगा। यदि शिकायत का विषय प्राप्त करने वाले मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तो इसे सही प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।

पीएम मोदी ने सचिवों के साथ की थी बैठक- इसमें कहा गया कि जिन मंत्रालयों/विभागों में बड़ी संख्या में जन शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां स्वतंत्र प्रभार के साथ पर्याप्त पद पर एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी जाती है, ताकि जन शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि संशोधित दिशा-निर्देशों का उल्लेख करने वाला यह आदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से 29 जून को भारत सरकार के सचिवों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया।

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस बार जन्माष्टमी अपने निवास पर दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई।

प्रमुख समाचार

शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही; मोदी ने किया था अनावरण

मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सोमवार को ढह गई। गौरतलब है कि इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, प्रतिमा मालवन स्थित राजकोट किले में दोपहर एक बजे ढही। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ प्रतिमा के ढहने के वास्तविक कारण का पता लगाएंगे। हालांकि, जिले में बीते दो-तीन दिनों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मौसम के कारण प्रतिमा अचानक ढह गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि पीएम मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर पिछले साल दिसंबर में प्रतिमा का अनावरण किया था। वह किले में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे।

कंगना रणौत के विवादित बयान पर बरष्टसे राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रणौत पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने सोमवार को कहा कि कंगना का विवादित बयान भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है। गौरतलब है कि भाजपा ने सोमवार को कंगना के उस बयान से किनारा कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थीं। भाजपा ने साफ किया था कि कंगना रणौत भाजपा के नीतिगत मसलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं और यह बयान उनका निजी था। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है।

हम गोंदिया और भंडारा में तीन सीट पर दावा करेंगे: राकांपा

गोंदिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) नेता अनिल देशमुख ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में उनकी पार्टी गोंदिया में तिरोरा, अर्जुनी मोरगांव और भंडारा में तुमसर विधानसभा सीट पर दावा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि महा विकास आघाडी(एमवीए), जिसमें राकांपा (एसपी) कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं, आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा और एकनाथ शिंदे सरकार को उखाड़ फेंकेगा। राकांपा (एसपी) कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लेने आए राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने कहा, ''हम इन तीन सीट पर दावा करेंगे क्योंकि वहां से हमारे मौजूदा विधायक हैं।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य मंत्री धरमराव अत्राम की बेटी भाग्यश्री अत्राम ने शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की थी और अहेरी से अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छुक थीं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, देशमुख ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। देशमुख ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें जिस सीट से कहेगी, वह वहीं से लड़ेंगे।

लद्दाख में पांच नए जिले बनाने की अमित शाह ने की घोषणा

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नए जिलों के निर्माण से लोगों को मिलने वाले लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। उन्होंने गृह मंत्रालय के इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दृष्टिकोण को श्रेय दिया। अपनी पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की खोज में, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले, ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्रालय के लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है।

मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षितः बीएसएफ

शिलांग। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कहा कि मेघालय में 443 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही बल ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश के दावों का खंडन किया। अर्धसैनिक बल ने उन खबरों के बाद एक बयान जारी किया, जिनमें पड़ोसी देश की मीडिया ने खबर दी कि अवामी लीग के नेता इशहाक अली खान पन्ना की अपने देश से भागने की कोशिश में मेघालय के दावकी में एक पहाड़ी पर चढ़ते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित दावकी, बांग्लादेश के निकट है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों का कोई अवैध प्रवेश नहीं हुआ है। पन्ना की मौत की जो कहानी फैलाई जा रही है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अवैध घुसपैठ या हमारे देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा।''

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव अगले माह, भारत और हिंद क्षेत्र के लिए भी अहम रहेंगे

सुधीर सक्सेना

छंदय यानी चुनाव। सिंहली-अंग्रेजी युग्म रचें, तो होगा छंदय-मोड। हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका इन दिनों छंदय मोड में है। एक महीने बाद 21 सितंबर को करीब एक करोड़ 70 लाख मतदाता विषम परिस्थितियों से गुजर रहे द्वीप-राष्ट्र का नया राष्ट्रपति चुनेंगे! बिसात बिछ चुकी है। पासे फेंके जा चुके हैं। वातावरण आवेशित है। दुविधा और संभ्रम की स्थिति है। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ी सुपरिचित हैं।

यों तो एक अनार के लिए बीमारों की संख्या 39 है, किंतु मुकाबले में मुख्यत: चार खिलाड़ी हैं। ये चार खिलाड़ी हैं-अनेक दलों का समर्थन प्राप्त, निवर्तमान राष्ट्रपति निर्दलीय प्रत्याशी रानिल विक्रमसिंघे, समागी जन बालवेगया के सजिथ प्रेमदासा, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के नमल राजपक्षे और जनता विमुक्ति पेरामुना के अनुरा कुमारा दिसानायके। इनमें पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके 75 वर्षीय रानिल वरिष्ठतम हैं, जबकि नमल की आयु सबसे कम 38 वर्ष है।

गौरतलब है कि श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार को स्वेच्छाचारी और एकाधिकारवादी माना जाता है। विगत संसदीय चुनाव में उसके पांच सदस्य जीते थे। महिंदा राजपक्षे बने प्रधानमंत्री, अनुज त्रयी गोटबाया राष्ट्रपति, चमल सिंचाई मंत्री, बेसिल वित्तमंत्री और पुत्र नमल खेलमंत्री। वर्ष 2022 में व्यापक जनाक्रोश राजपक्षे परिवार के पतन का कारण बना। यों तो रानिल सत्ताच्युत गोटबाया राजपक्षे की पसंद थे, लेकिन वक्त ने रानिल पर गोटबाया के भरोसे की चूलें हिला दी है। इसलिए उन्होंने युवा नमल को मैदान में उतारा है। विधि में स्नातक नमल एसएलपीपी के %पोस्टर ब्वॉय हैं। उन्हें मिले वोट से पता चलेगा कि अधिनायक-वृत्ति और स्वेच्छाचारिता के बावजूद श्रीलंकाई लोग राजपक्षे परिवार को कितना पसंद करते हैं?

पिछले दो दशकों से श्रीलंका में सत्ता की चाबी राजपक्षे परिवार के हाथों में है। लेकिन अरागलिया विद्रोह ने राजपक्षे परिवार के पांवों तले से जमीन खींच ली। एकबारगी लगा कि महिंदा पलायन को बाध्य होंगे, लेकिन कूचे से बेआबरू होकर निकलने की अटकलों के बीच उन्हें पूर्वोत्तर प्रांत के नौसैनिक अड्डे त्रिंकोमाली में मुकम्मल सुरक्षा मिल गई। राजपक्षे घराना फौजी हिफाजत में तबसे वहीं रह रहा है।

श्रीलंका में चीन की रुचि और भारत को घेरने की उसकी कोशिशें किसी से छिपी नहीं हैं। चीन से राजपक्षे का मोह अब भी कायम है। 27 जून, 2024 को महिंदा चीन के विदेश मंत्री वांग के न्यौते पर बीजिंग गए थे। वहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। फिर उनकी चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग से ऋण पुनर्गठन मसौदे पर भी चर्चा हुई। कहना कठिन है कि महिंदा और चीनी नेताओं के बीच चुनाव और भावी राजनीति को लेकर क्या खिचड़ी पकी, लेकिन इस बाबत महिंदा की चुप्पी अटकलें पैदा करती है।

भारत और श्रीलंका के रिश्ते गर्भनाल सरीखे हैं। जातीय और सांस्कृतिक संदर्भ भारत-श्रीलंका मैत्री को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। श्रीलंका का भारत के लिए अतिरिक्त सामरिक महत्व भी है। भारत ने भयावह वित्तीय संकट का सामना करने में कोलंबो की भरपूर मदद की। श्रीलंका के घटनाक्रम पर भारत की पैनी निगाह है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो जाने पर महिंदा राजपक्षे से मुलाकात और चर्चा की। बीते फरवरी में जनता विमुक्ति पेरामुना के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मिले थे।

अनुरा दिसानायके वामपंथी सोच के मुखर नायक हैं और इस छंदय-द्वंद्व में चमकीली संभावना बनकर उभरे हैं। बहुत संभव कि वह कोलंबो की सत्ता की पेचीदा लड़ाई में दिल्ली की परोक्ष पसंद बनकर उभरें। अनुरा राजधानी कोलंबो से सांसद हैं और भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम के पुरोधा भी हैं। भौतिकी में स्नातक अनुरा एक श्रमिक के बेटे हैं और वर्ष 2015-18 में मैत्रीपाल सिरिसेना के काल में मुख्य विपक्षी सचेतक रहे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से रिश्तों को लेकर उनका रुख रानिल से सर्वथा भिन्न है।

रानिल की चमक और खनक अब पहले जैसी नहीं रही। एक तो उनकी छवि राजपक्षे-कुनबे के पिछलग्गू की है, दूसरे मितव्ययिता के सख्त उपायों के कारण वह अलोकप्रिय हो चुके हैं। बहरहाल, लड़ाई रोचक है, श्रीलंका के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र के लिए बहुत मानीखेज। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में श्रीलंका की युवा-शक्ति और सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

लाखों लेने के आरोप में घिरे एमआईसी सदस्य राजेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा

राजनांदगांव। विधानसभा टिकट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए लेने के आरोप में घिरे राजनांदगांव नगर निगम के एमआईसी सदस्य राजेश गुप्ता (चंपू) ने मेयर इन काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने एमआईसी की सदस्यता से इस्तीफा देने की पुष्टि की है, साथ ही गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नई दिल्ली में केसी वेणुगोपाल को भी त्यागपत्र देने की जानकारी भेजी है।

गुप्ता पिछले निकाय चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे। महापौर हेमा देशमुख की टीम में वह विधि विधायी विभाग के चेयरमेन थे। पिछले दिनों रुपए लेकर टिकट दिलाने और घर में जुआ खिलाने के दौरान फरार होने के मामले में वह सुर्खियों में थे। सोमवार को गुप्ता ने अपने बच्चों के जरिये शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा को इस्तीफा भेजा। हालांकि गुप्ता को नियमानुसार महापौर को इस्तीफा देना चाहिए था।

उधर, महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि गुप्ता कांग्रेस के सदस्य नहीं थे इसलिए उनके एमआईसी से इस्तीफे की जानकारी से वह अनभिज्ञ है। उधर पुलिस रुपए लेकर टिकट दिलाने के मामले में अपराध दर्ज करने के बाद गुप्ता की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इधर राजेश गुप्ता चंपू ने शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा को भेजे त्यागपत्र में उल्लेख करते बताया कि महापौर की कार्यप्रणाली, वार्ड विकास के भेदभाव व अडियल रवैये के चलते वह महापौर परिषद से इस्तीफा दिया। उन्होंने त्यागपत्र में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद शहरी सरकार में कांग्रेस की हेमा देशमुख के महापौर रहते उसके वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं हो सका, जिसे गिनाया जा सके या इतिहास के पन्नों में पर दर्ज करने योग्य हो? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वार्ड नं. 41 स्थित इंदिरा नगर के पीछे बना आधा-अधूरा नाला निर्माण घोटाले को लेकर 2021 से लगातार प्रमुखता से उठाया जाता रहा? कागजों पर बना तीस करोड़ रुपए की लागत से बना नाला को लेकर उक्त नाले का चौड़ीकरण करने व नला के ऊपर आसपास हुए प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता को सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा गया था।

उद्यान अधीक्षक की मनमानी, सरकारी नर्सरी में जड़ दिया ताला

■ विरोध में उतरे कर्मचारी

आरंग। रायपुर के आरंग ब्लॉक के अंतर्गत पारागांव में शासकीय उद्यान रोपणी (नर्सरी) में उद्यान अधीक्षक की मनमानी का मामला सामने आया है। अधीक्षक ने बिना किसी नोटिस के या लिखित आदेश के आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर के बहाने नर्सरी में अंदर से ताला लगवा दिया, जबकि अन्य नर्सरी में काम जारी है। जिसके बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वरोध पर उतर आए हैं।

कर्मचारियों ने बताया कि जब वे रोज की तरह काम पर पहुंचे, तो गेट में ताला लगा हुआ था। जानकारी मिलने पर पता चला कि उद्यान अधीक्षक ने जन्माष्टमी के अवकाश का हवाला देते हुए नर्सरी को बंद करवा दिया। कर्मचारियों ने नाराजगी जताई कि वे हमेशा अवकाश के दिनों में भी कार्य करते हैं और उन्हें उचित वेतन भी मिलता है।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने यह भी बताया कि पारागांव नर्सरी को छोड़कर अन्य ब्लॉकों और जिलों की नर्सरियों में कामकाज सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्यान अधीक्षक द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के जन्माष्टमी के बहाने उन्हें काम करने से रोका जा रहा है।

ग्रामीणों और सरपंच की नाराजगी

इस विवाद को लेकर ग्राम पंचायत पारागांव के सरपंच नारायण पाल भी नर्सरी पहुंचे। उन्होंने मोबाइल के माध्यम से उद्यान अधीक्षक से नर्सरी को खोलने और कर्मचारियों को काम सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस रवैये से न केवल कर्मचारियों में, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में भी नाराजगी फैल गई है।

आंदोलन की चेतावनी

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता, तो वे उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।

अधीक्षक ने किया आश्वस्त

उद्यान अधीक्षक एनके सरकार का कहना है कि जन्माष्टमी के अवकाश और अति महत्वपूर्ण कार्य न होने के कारण दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छुट्टी दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले दिन से काम सामान्य रूप से चलेगा।

विश्व हिंदू परिषद ने मनाया स्थापना दिवस

बलरामपुर रामानुजगंज। रामानुजगंज में विश्व हिन्दू परिषद के स्थापना दिवस सप्ताह कार्यक्रम के तहत हिन्दू समाज को संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से विचार गोष्ठी आयोजित किया गया। हिन्दू समाज को एकजुट करने समेत गौहत्या एवं धर्मांतरण को रोकने पर भी चर्चा हुई। जाति के भेद को दूर कर सभी हिन्दुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विश्व हिन्दू परिषद के विभाग समरसता प्रमुख ललन कुशवाहा ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर रामानुजगंज में कार्यक्रम रखा गया। वीएचपी की 1964 में हुई स्थापना से लेकर अब तक हम संगठन का स्थापना दिवस मनाते रहे हैं। हम सभी संकल्पित हुए हैं कि अपने धर्म राष्ट्र की सेवा और कर्तव्य निभाते रहेंगे। वीएचपी की तरफ से आयोजित इस बैठक के संबंध में जिला सह मंत्री आकाश तिवारी ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद के स्थापना दिवस पर जिले भर से वरिष्ठ जनों का आना हुआ। इस दौरान ये संकल्प लिया गया कि सर्व हिन्दू समाज को एकजुट करके वीएचपी के माध्यम से बेहतर कार्य किया जाएगा।वीएचपी की स्थापना का उद्देश्य = विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना साल 1964 में जन्माष्टमी के दिन की गई थी। इसका उद्देश्य हिन्दू समाज को एकजुट करना, मजबूत करना हिन्दू धर्म की सेवा और सुरक्षा करना है। साथ ही गौहत्या और धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकना है।

आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नियमों में केंद्र सरकार की नीतियों को हाईकोर्ट ने ठहराया सही

विदेशी छात्रों की याचिका खारिज

बिलासपुर। केंद्र सरकार के आईआईटी और एनआइटी में एडमिशन के नियमों को बदलने पर ऐतराज जताते हुए विदेशी छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. यह याचिका सऊदी अरब में रहने वाले 8 से अधिक छात्रों ने लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केंद्र सरकार का विषय और अधिकार है। इसमें छूट देना सरकार का नीतिगत निर्णय है। छूट के लिए दावा नहीं किया जा सकता है।

दरअसल, सऊदी अरब में रहने वाले स्टूडेंट्स शेख मुनीर, सुहास काम्मा, श्रियांस कुमार, आफिया अनीस, रंजीत, राघव सक्सेना सहित अन्य ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें विदेश स्टूडेंट्स ने कहा था कि एनआईटी, आईआईटी और अन्य संस्थानों में डासा योजना के तहत एडमिशन के लिए पात्र हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित मानदंड में बदलाव किया है इसके चलते वे एडमशिन नहीं करा पा रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए स्नातक कोर्स में एडमिशन के लिए पूर्व में 60 फीसदी अंक निर्धारित किया गया था। 30 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत डासा योजना से एडमिशन के लिए निर्धारित अंकों में बदलाव किया गया, और इसे बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसे अनिवार्य शर्त में शामिल कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2001-02 में विदेशी नागरिकों, भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले, अप्रवासी भारतीयों और एनआरआई को देश के प्रमुख 66 तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए डासा योजना लागू की गई है।

माफिया ने काटे 300 से अधिक नीलगिरी के पेड़

केस दर्ज कर जांच में जुटी वन विभाग की टीम

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल के पथरा वन बीट के शासकीय भूमि पर लगे प्लांटेशन के लगभग 300 सामान्य प्रजाति के वनों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। मामले पर वन मंडल अधिकारी डीएफओ सहित वन अमला मौके में पहुंचकर सभी पेड़ों को जब्त कर अवैध कटाई करने वाले के खिलाफ वन अपराध सहित अवैध परिवहन का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पथरा गांव का है, जहां शासकीय भूमि पर वन विभाग ने वर्षों पहले प्लांटेशन के माध्यम से नीलगिरी के पौधे का वृक्षारोपण किया था। संघन वृक्षारोपण के साथ समय के साथ वृक्ष बड़े एवं हर हो गए थे। हालांकि यह सभी वृक्ष गैर राष्ट्रीयकृत थे, परंतु पथर्रा गांव के लोग इस जंगल एवं जमीन पर निस्तार का काम करते थे। जंगल जमीन की रक्षा करने के उद्देश्य से लगे हरे भरे प्लांटेशन पर गांव के ही वन माफिया की नजर लग गई और वह और वह हाथ मशीन से लगभग 300 से अधिक नीलगिरी के पेड़ों को काटकर गिरा दिया।

ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए वन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी। मरवाही वन मंडल का समस्त स्टाफ सहित मरवाही वन मंडल की वन मंडल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अवैध कटाई करने वाले के खिलाफ वन अपराध दर्ज करते हुए जंगल की भूमि से अवैध परिवहन का मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी वन विभाग गणना के बाद ही देगा।

15 साल से कर रहे हैं पुल निर्माण की मांग

तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया था आश्वासन

कांकेर। कांकेर जिले के परवी गांव से खड़का के बीच मंघर्रा नाला पर पुल नहीं है। यहां पुल निर्माण की मांग ग्रामीण 15 साल से कर रहे हैं। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ग्रामीणों की मांग पर पुल निर्माण के लिए आश्वासन दिया था लेकिन पुल नहीं बना। 2019 में सरकारे बदली। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुल निर्माण के लिए घोषणा की थी फिर भी पुल नहीं बना। तीन गांव खड़का, भुरका और जलहुर के ग्रामीणों ने खुद कुल्हाड़ी उठाई और बांस बल्ली का प्रबंध कर श्रमदान करते कच्चा पुल तैयार कर दिया. रोजमर्रा के सामान के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता था. एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें 10 किमी की जगह 45 किमी चक्कर लगाना पड़ता था।

दरअसल जिला मुख्यालय कांकेर से 70 किलोमीटर दूर तीन गांव खड़का, भुरका और जलहुर ये तीन गांव के ग्रामीण आजादी के बाद से लगातार मंघर्रा नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे है. ग्रामीणों ने बताया कि नदी के बहते पानी को पार कर आना जाना करते है. लेकिन बारिश का मौसम अधिक कठिनाई भरा रहता है. ग्रामीणों ने बांस और बल्ली की मदद से एक स्थाई पुल बना लिया है. जिससे अब वह आना जाना कर रहे है।

ग्रामीणों का कहना है कि तीनो गांव बारिश के 4 महीने टापू में तब्दील हो जाते है. नदी में बारिश का पानी आ जाने से आना- जाना बंद हो जाता है. दूसरे मार्ग से जाने से 45 किमी सफर करना पड़ता है. ग्रामीण अपने गांवो में फंसे रह जाते है. ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग नही कि हो. शासन, प्रशासन, विभिन्न जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में अवगत कराकर मांगे की जा चुकी है. पर अब तक उनकी नही सुनी गई. इसलिए ग्रामीणों ने बांस और बल्ली की मदद से लकडी का पुल बनाया है। ग्रामीण महिला ने बताया कि किसी गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कत होता है. स्वास्थ्य सुविधाओं का वाहन गांव तक नही पहुंच पाता है. कांवड़ से महिलाओं को ले जाते है। यही हाल स्कूली बच्चो का है. पानी ज्यादा होने से स्कूली बच्चे स्कूल नही जाते है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण को मारा

बीजापुर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जैगुर निवासी ग्रामीण पर नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना है। इस वारदात को नक्सलियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने दिया है। बता दें कि नक्सलियों के द्वारा जारी अपने पर्चे में बताया कि 2021 से मंडावी सीतु मुखबिरी का काम कर रहा था, जिसे देखते हुए उसे जन अदालत में जान से मारने का फरमान जारी किया गया था, इसके अलावा नक्सलियों के द्वारा ऑपरेशन कगार को हराने की बात भी कही है। फर्जी मुठभेड़ को बंद करने की बात कही है, भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम जैगुर निवासी था मृतक। 26 अगस्त को सीतु को मौत की सजा दी गई है।

मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प

अंबिकापुर। शहर के ईरानी मोहल्ले में बीती देर रात मामूली विवाद के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस घटना से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है।

खेरथा सरपंच की धारदार हथियार से की गई हत्या

बालोद। लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजारी चौकी के ग्राम क्षेत्र बाजार से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सरपंच की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी का माहौल है। युवा सरपंच का नाम विक्रम सिन्हा है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। सरपंच की लाश एक व्यक्ति के घर में मिली है। वहीं, आने वाले कुछ महीने में सरपंच का चुनाव भी होने वाला है। कार्यकाल के अंतिम समय में उसकी हत्या की गई है। पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, सरपंच विक्रम सिन्हा के कथित मित्र राम जी प्रजापति के घर पर लाश मिली है। राम जी प्रजापति गांव में कहता हुआ घूम रहा है कि हत्या उसने की है, लेकिन उसके द्वारा कारण नहीं बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा घटनास्थल क्राइम सीन को सील कर दिया गया है। यहां पर अब फोरेंसिक की टीम का इंतजार है। बताया जा रहा है कि फोरेंसिक की टीम पहुंचने वाली है। सूत्रों से पता चला है कि राम जी प्रजापति सरपंच विक्रम सिन्हा का दोस्त था।

महिला का कंकाल मिलने से मची सनसनी

कांकेर। कांकेर जिले के गढ़िया पहाड़ में एक महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के कंकाल के पास टूटी चूड़ियां और चांदी का पायल भी मिला है। पास ही साड़ी में लिपटा हुआ कंकाल मिला है। कांकेर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांकेर कोतवाली प्रभारी मनीष नागर ने बताया कि गढ़िया पहाड़ में महिला का नरकंकाल मिला है। फोरेंसिक और डॉग स्कॉड की टीम पड़ताल कर रही है। थाने में गुम इंसान की सूचना का रिकॉर्ड खंगला जा रहा है। आगे की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि महिला के पैर की हड्डी में पायल और हाथ की हड्डी में टूटी हुई चूड़ियां बरामद की गई हैं। कांकेर पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। गौरतलब है कि गढ़िया पहाड़ में रोजना सैकड़ो पर्यटक पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इससे पहले भी पहाड़ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं।

कमरे में अंगीठी जलाकर सो रही पुष्पा मंडल की दम घुटा

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम संतोषीनगर पिपराही में घर में अकेले रह रही वृद्ध महिला रात में अंगीठी जलाकर सोई थी। घुटन से उसकी मौत हो गई। वहीं, आग बिस्तर में पकड़ने के बाद सिर भी बुरी तरीके से जल गया है। घटना की सूचना पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव, भाजपा नेता अमित गुप्ता मंटु सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटना पर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार, संतोषी नगर पिपराही में वृद्ध महिला पुष्पा मंडल (65) घर में अकेले रहती थी। वह खेती बाड़ी का कार्य करती थी। रविवार रात खाना खाकर सोई थी। वहीं, उन्होंन खटिया के नीचे अंगीठी जला दी थी। बताया जा रहा है कि घर में खिड़की नहीं थी और दरवाजा बंद था। घुटन से उसकी मौत हो गई। वहीं, बिस्तर में आग पकड़ने के बाद खटिया एवं बिस्तर जलने से सिर भी बुरी तरह से जल गया।

जन्माष्टमी में सूना पड़ा अंबिकापुर का कृष्ण कुंज

■ पेड़ों के बीच अकेले खड़ी मुरधीधर की मूर्ति, कई दिनों से नहीं खुला गेट का ताला

सरगुजा। साल 2022 में भूपेश सरकार के दौरान 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पर त्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया. प्रदेश के 162 नगरीय निकाय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज बनाए गए। सभी कृष्ण कुंज में भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगाई गई। इनमें 383 औषधीय पौधे रोपे गये। जन्माष्टमी का उत्सव कृष्ण कुंज में बड़े धूम धाम से मनाया गया। बाद में साल 2023 में सत्ता बदल गई। ना ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और ना ही अभी की भाजपा सरकार ने इसकी सुध ली।

सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी था। कृष्ण मंदिरों में पूजापाठ, हवन कीर्तन हुआ। लेकिन अंबिकापुर का कृष्णकुंज वीरान पड़ा है। मीडिया जब कृष्णकुंज पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। ताले में भी जंग लग चुकी है। जो इस बात का संकेत दे रही है कि कई महीनों से कृष्णकुंज के गेट का ताला नहीं खुला है। वहां कई औषधीय पौधे लगाए गए है लेकिन उनका कोई केयर टेकर नहीं है।

वृक्षारोपण के बीच मे भगवान कृष्ण की प्रतिमा अकेली खड़ी है। जन्माष्टमी पर पूरे कृष्ण कुंज में सन्नाटा पसरा हुआ है।

कांग्रेस ने कहा- भाजपा को सिर्फ राम से मतलब

कांग्रेस नेता हिमांशु जायसवाल ने इस मामले में भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में कृष्ण कुंज के साथ राम वन गमन परिपथ भी बनवाया था। लेकिन भाजपा सिर्फ राम के नाम पर सियासत करती है। उसे वास्तविक में भगवान से कोई लेना देना नही है।

भाजपा का जवाब- कांग्रेस ने राम को बताया काल्पनिक

कृष्ण कुंज की बदहाली पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता वेदांत तिवारी कहते हैं कांग्रेस को इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही दल है जिसने रामसेतु के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी और भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में कृष्ण कुंज बनवाया, जबकि उनके पिता राम विरोधी हैं। रही बात कृष्ण कुंज बंदहोने की तो वन विभाग के अधिकारियों से बात कर उसे जल्द खुलवाया जाएगा।

पीडीएस चावल की खरीदी-ब्रिकी की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी

प्रोपराइटर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

कांकेर। कांकेर में पीडीएस के चावल की हर महीने बड़ी मात्रा में हेराफेरी होने का मामला सामने आया है। खाद्य और राजस्व विभाग को शिकायत के बाद एसडीएम अशोक कुमार मारबल ने अचानक छापा मार कार्रवाई की।

राजस्व, पुलिस और खाद्य अफसरों की संयुक्त टीम ने कृषि मंडी अन्नपूर्णपारा के सामने सूचना के आधार पर छापा मार कार्रवाई की। शिकायत मिली थी कि केजीएन चावल दुकान के यहां पीडीएस के चावल की खरीद फरोख्त होती है। वहां 11.50 कुंतल (23 बोरी) पीडीएस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी यानी गरीबों को बांटने वाला फोर्टीफाइड मोटा चावल मिला। साथ ही सात बोरियों में शासन द्वारा दी जाने वाला चना मिला है। कुछ बोरियो में चना पैकेट में भी था।

एसडीएम ने उस दुकान के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक कांकेर को थाना में एफआईआर दर्ज करने निर्देशित किया है। खाद्य विभाग ने आगाह किया है कि राशन का चावल अवैध तरीके से बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉ. वाणी ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां

राजभवन में मौसम विज्ञान केंद्र के छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉ. गायत्री वाणी और श्री कंदन मुर्मू ने सौजन्य मुलाकात की।

रिलायंस मार्ट से रसोई का किराना सामान चुराने वाला गिरफ्तार

रायपुर। मोवा में स्थित रिलायंस मार्ट से रसोई का किराना सामान चुराकर खाने वाले मध्यप्रदेश के अनुपपुर में रहने वाले युवक को पंडरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सामान खा लेने के लिए पुलिस ने उसके खम्हारडीह के घर से कोई भी सामान जप्त नहीं कर सका। पंडरी पुलिस ने बताया कि रिलायंस मार्ट कर्मी ने शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मार्ट में एक युवक अपने साथ बैग लेकर आता है और बताता कि इसमें कीमती सामान है इसलिए वह उस बैग को गेट पर जमा नहीं कर सकता। और भीतर ले जाकर वह उसी बैग में रिलायंस मार्ट में उपलब्ध दैनिक उपभोग की सामग्री को चुपके से चुराकर बैग में डाल देता था। स्टोर से निकलने के दौरान केबल टाई बैग में लगी रहती थी जिस वजह से युवक पकड में नहीं आता था। सीसीटीवी की जांच से पता करने पे पता चला कि कई बार उसी युवक ने इसी तरीके से स्टोर के समान को बिना बिल कराये लेकर चला जाता था। इस रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस मे रिलायंस मार्ट मोवा के सीसीटीवी फुटेज से युवक की पहचान राज कुमार सोनी पिता गेंदलाल सोनी उम्र 37 वर्ष निवासी कचना थाना खम्हारडीह,, तथा स्थायी पता पुरानी बस्ती वार्ड 13 अनुपपुर म.प्र. के रूप में कर पकड़ा गया। मार्ट कर्मियों के बयान पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने चोरी और सभी सामानों को उपभोग कर खत्म कर देना बताया जिसे गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया।

बड़ा हादसा टला, चलती मालगाड़ी से रैक अलग होने से मचा हड़कंप

रायपुर। राजधानी के मोहबा बाजार के पास बड़ी रेल दुर्घटना टली गई। दरअसल, चलती हुई मालगाड़ी से रैक अलग हो गया। इस बात का अहसास होते ही मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड के जरिए अधिकारियों तक सूचना पहुंची, जिसके बाद रैक को जोड़कर मालगाड़ी रवाना हुई।

इस बार दिखेगी 7 फीट से लेकर 30 फीट तक भगवान गणेश की मूर्तियां

रायपुर। गणेश चतुर्थी का खास पर्व जल्द ही शुरू होने वाला है। जिसके जश्न की तैयारी पूरे देश में बड़े स्तर पर की जा रही हैं। इस बार 7 सितंबर से पूरे देश में जगह-जगह पर सार्वजनिक पंडाल में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। जिसके बाद 10 दिनों तक भगवान गणेश इन पंडालों में विराजमान रहेंगे। हर बाद की तरह ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस बार अलग-अलग थीम में भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं देखने को मिलने वाली हैं। रायपुर में इस बार 7 फीट से लेकर लगभग 30 फिट की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। गणेश जी की प्रतिमाएं बनने का काम लगभग पूरा हो गया है। इन प्रतिमाओं का रंगरोगन भी किया जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए मूर्तिकार शपन मंडल ने बताया की इस बार रायपुर में अलग-अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलेगी। हमारे यहां लगभग 7 हजार से लेकर एक लाख 50 हजार रुपए तक की मूर्तियां हैं। जिसकी लंबाई 7 फीट से लेकर लगभग 20 से 22 फीट तक की होती है। यहां एक साल पहले से बुकिंग शुरू हो चुकी है। मूर्ति बनाने के लिए कारीगर कोलकाता और बंगाल से भी आए हुए है।

स्पोर्ट्स कोर्ट बनकर तैयार, बैडमिंटन, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेल सकेंगे बच्चे

रायपुर। राजधानी रायपुर को अवैध कब्जे से बचाने के लिए मुंबई, भोपाल, गाजियाबाद, कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे महानगरों की तर्ज पर रायपुर में ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एक्सप्रेस वे ओवरब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग करने यह स्पोर्ट्स मैदान बनाया गया है, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेला जाएगा। बारिश के दौरान भी यहां बच्चे बिना किसी परेशानी के खेल सकेंगे। स्पोर्ट्स कोर्ट बनने से न केवल बच्चों को खेल का मैदान मिला है बल्कि ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन अवैध कब्जे से भी सुरक्षित हुई है। स्पोर्ट्स कोर्ट लगभग 1 माह के भीतर बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन में राजधानी के बच्चे यहां अलग-अलग तरह से गेम खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई और गाजियाबाद की तर्ज पर अंडरब्रिज के नीचे बनाए गए रहे इस मैदान में खिलाड़ी रात और दिन दोनों समय खेल सकेंगे। ओवरब्रिज के नीचे बनाए गए इस मैदान में एक मैदान तो बैडमिंटन और बॉस्केटबाल के लिए है। वहीं दूसरा वालीबॉल के लिए बनाया गया है।

स्पीकर हाउस बनेगा साहित्य और संस्कृति का केंद्र : डॉ. रमन

आशीष ठाकुर लिखित दस्तावेजी किताब 'रायपुर' का डॉ. रमन सिंह ने किया विमोचन

रायपुर । स्पीकर हाउस में सोमवार को हरि ठाकुर स्मारक संस्थान की ओर से पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया। रायपुर नामक दस्तावेजी किताब का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने किया। किताब का लेखन वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार आशीष ठाकुर ने किया है। विमोचन के मौके पर विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इतिहासकार, साहित्यकार, रंगकर्मी और पत्रकार भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

डॉ. रमन सिंह ने किताब के लेखक को बधाई देते हुए कहा कि रायपुर नगर के इतिहास पर आशीष सिंह ने जी ने बड़ा काम किया है। रायपुर प्राचीनकाल से ही ऐतिहासिक नगर रहा है। रायपुर को अलग-अलग कालखंडों में कई नाम दिए गए। जैसे कभी इसे कंचनपुर, कभी कनकपुर कहा गया। इससे पता चलता है कि रायपुर की महत्ता सोने के समान रहा है। रायपुर को रयपुर भी कहा जाता रहा है। रय का अर्थ माता लक्ष्मी और पुर का अर्थ निवास होना भी बताया गया है। अर्थात वह स्थान जहां माता लक्ष्मी का निवास हो।

डॉ. रमन सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास के पन्नों में रायपुर और राज्य का गौरवशाली पन्ना बिखरा हुआ है। इन पन्नों को सहेजने का काम हम सबकों मिलकर करना होगा। पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक के रायपुर को बताने और दिखाने का काम करना होगा। रायपुर के अंदर ढेरों ऐतिहासिक धरोहर और

निशानियां हैं। रमन सिंह ने इस दौरान कल्चुरी राजवंश, किला, बूढ़ा तालाब, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग और बाबूलाल टॉकिज से जुड़े हुए किस्सों के साथ ही उन्होंने 70 के दशक में रायपुर में हुई कॉलेज की पढ़ाई के दिनों को भी साझा किया।

डॉ. रमन सिंह ने इस दौरान यह घोषणा भी की स्पीकर हाउस को हम साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनाएंगे। राज्य के साहित्यकार, लेखकर, संस्कृतिकर्मी अगर कोई साहित्यिक आयोजन, किताब का विमोचन कराना चाहते हैं तो वें स्पीकर हाउस में कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं। इसकी सुव्यवस्था हाउस के अंदर मौजूद सभागार में की जा रही है। आयोजन के लिए कम से कम सप्ताहभर पूर्व एक सूचना देनी होगी। मैं एक बेहतर आयोजन के लिए साहित्यकारों और लेखकों को आमंत्रित करता हूँ कि वें निरंतर इस दिशा में प्रसात करते रहें।

पुरखों की स्मृतियों को संजोने हम संकल्पबद्ध- विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आशीष भैय्या ने जो ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया वह महत्वपूर्ण है। मैं इस किताब के लेखन के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं किताब को अभी पढ़ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन पन्ने पलट ही रहा था कि मेरी नजर रायपुर लगर के सौ साल पुरानी एक इमारत पर पड़ी। इससे यह पता चलता है कि रायपुर नगर शताब्दी पूर्व कैसा रहा होगा। इसी तरह के प्रयास हम सबको मिलकर करना है। अतीत के पन्नों को पलटने से वर्तमान को भविष्य का ज्ञान हो सकता है। कहने का अर्थ है की नई पीढ़ी के समक्ष दस्तावेजी इतिहास को सामने लाते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल तक जब डॉ। रमन सिंह की सरकार थी तब भी पुरखों की स्मृतियों को संजोने का काम हुआ और वर्तमान में आज फिर से भी बीजेजी की सरकार है तो मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुरखों की स्मृतियों को संरक्षित, संवर्धित करने हम संकल्पबद्ध हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार डॉ। रामकुमार बेहार ने की। उन्होंने कहा कि आशीष ठाकुर जी ने रायपुर नामक इस किताब से छत्तीसगढ़ के कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। यह एक शोधपरक किताब है। वहीं इतिहासकार डॉ। एल.के। निगम ने कहा कि सरकारों को ऐसे किताबों का संदर्भ लेकर ऐतिहासिक स्मारकों, दस्तवेजों को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। इतिहासकार डॉ। रमेन्द्रनाथ मिश्र ने कहा कि रायपुर नगर इतिहास अत्यंत प्राचीन है। रायपुर के अंदर ही अभी कई स्थानों पर खुदाई करने से अतीत के कालखंड बाहर आने लगेंगे। रायपुर सदियों पूर्व से एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी रहा। संस्कृति विशेषज्ञ अशोक तिवारी ने कहा कि इस किताब में कई कालखंडों का उल्लेख है। मैं किताब के लेखक दस्तावेजी लेखन के लिए बधाई देता हूँ। इस बहाने यह भी कहूँगा कि किताब के लिए जरिए जिन ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र किया गया उसे संरक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि इस रायपुर नगर से पहली सरकारी बिल्डिंग जो कि एक धरोहर था उसे हम खो चुके हैं।

विमोचन कार्यक्रम में साहित्यकार डॉ। सुशील त्रिवेदी, डॉ। सुधीर शर्मा, शकुंतला तरार, जागेश्व प्रसाद, रंगकर्मी अरविंद मिश्रा, राकेश तिवारी, कवि मीर अली मीर, सहित कई अन्य साहित्यकार, पत्रकार, रंगकर्मी और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।

छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और नक्सलवाद को लेकर विजय शर्मा का बयान, कहा-

नक्सलवाद खात्मे को लेकर प्राण और मन से जुटेगी प्रशासन

रायपुर। रायपुर में प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सितंबर से पुलिस महकमे में एक बड़ी पहल की जाएगी। इसके तहत सभी रेंज के एसपी ऑफिस में बैठकें की जाएंगी, जिनमें एसपी और थानेदारों के की-परफॉरमेंस तय की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2021 से 2023 तक के आंकड़ों की तुलना में 2024 के जनवरी से जून तक अपराधों की संख्या कम है, लेकिन यह संतुष्टि का विषय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम अपराध भी सरकार और समाज के लिए चिंता का विषय हैं, और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी।

वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के अमित शाह के आगामी कुछ महीनों में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दिये गए बयान को लेकर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प बड़ा है। पिछले कुछ महीनों में अभियानों के तहत जवानों ने कमाल कर दिखाया है, सभी प्रशंसा के हकदार हैं। हम नक्सलवाद से देश और प्रदेश को मुक्त कराने के लिए प्राण और मन से जुटेंगे। उन्होंने कहा कि तय

समय सीमा में बस्तर के लोगों और गांव के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक विश्वास जीतने में समय लगता है, और जंगल से लौटने के बाद जीवन को व्यवस्थित करना कठिन होता है। इसलिए, सरेंडर पॉलिसी में और भी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि सरेंडर करने वाले लोग जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी बताया कि बस्तर के सरेंडर किए गए लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाता है, जहां उन्हें सात दिन के अंदर गन पकड़ाकर गनमैन बनाया जा सकता है। बस्तर के लोग विश्वसनीय होते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटते। हालांकि, जंगलों में लंबा समय बिताने के बाद जीवन को फिर से व्यवस्थित करने में कठिनाइयां आती हैं, जिसके समाधान के लिए यह पहल की जा रही है।

नक्सलवाद खात्मे को लेकर उन्होंने बताया कि बस्तर में चार आयामों पर काम हो रहा है। 13 से 18 साल के बच्चों और जवानों को घर से उठाकर नक्सली बना दिया जाता है, इसके लिए भी गतिविधियां की जा रही है। पीड़ितों के लिए कुछ एनजीओ सामने आये हैं और सरकार की ओर से भी काम हो रहा है। सभी पर कार्य किया जा रहा है। बस्तर के लोग सुरक्षित और उनकी संस्कृति संरक्षित रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

पीडब्ल्यूडी संविदा कर्मी करेंगे उग्र प्रदर्शन

रायपुर। पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर 4 सितंबर को ईएनसी पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इस घेराव में पूरे प्रदेश के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जिसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ नेतृत्व किया जाएगा।

संघ के सदस्य भूषण साहू ने बताया कि हम लोग लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अनियमित कर्मचारी हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 6000 संख्या है। उनमें से आधे लोगों को सम्मान राशि दी जा रही है। इनकी संख्या लगभग 4000 है, जो बाकी के 2000 लोगों को सम्मान राशि नहीं दी जा रही है।

सदस्य भूषण साहू ने कहा हमारा पीएफ भी नहीं कट रहा है। यदि हमारा पीएफ कटता है तो इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। भूषण ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग 4 सितंबर को ईएनसी पीडब्ल्यूडी का घेराव करने वाले हैं।

क्या है संघ की मांगें ?

1. श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि का लाभ दिया जाए। 2. श्रमिकों का वेतन भुगतान माह के 5 तारीख तक किया जाए। 3.कार्य से पृथक किए गए श्रमिकों की जल्द से जल्द कार्य वापसी की जाए। 4. श्रमिकों को ईपीएफ का लाभ जल्द से जल्द मिले। 5. श्रम सम्मान राशि का भुगतान माह के 30 तारीख तक किया जाए। 6. अभनपुर उपसंभाग के श्रमिकों को 30 दिनों का वेतन दिया जाए। 7. सामान्य भविष्य निधि कटौती का आदेश प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया जाए।

नवा रायपुर में नामकरण के लिए समिति पर सियासत, बैज बोले -

नाम बदलने और काम बंद करने के सिवा कुछ नहीं कर रही सरकार

रायपुर। नवा रायपुर में नामकरण को लेकर गठित समिति पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, सरकार सरकारी योजनाओं को बंद करने, नाम बदलने में टाइम पास कर रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है।

कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू किए जाने को लेकर बैज ने कहा, कर्मचारी हित की बात करते रहे, अटल बिहारी की सरकार में ओल्ड पेंशन को बंद किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई। आज बढ़ते दबाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया गया। इसमें भी नाम बदल दिए, कोई नया चीज नहीं है।

नशे के खिलाफ सख्ती को लेकर अमित शाह ने बैठक ली, इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, अमित शाह को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते। शराब से बीजेपी के नेताओं को कमीशन जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं।

अमित शाह का बयान छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाला है।

संगठन में युवाओं को मिलेगा मौका

कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर दीपक बैज ने कहा, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे, युवाओं से काम लेंगे। हम लोगों ने सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी है। जनहित के मुद्दे उठाना है इसलिए मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। बीजेपी संगठन खुद नहीं चला पा रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं।

गौवंशों की रक्षा के लिए सरकार गंभीर नहीं

कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में गौवंश हादसे के शिकार हुए, इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी के नेता अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये असल में फर्जी है। लगातार गौ वंशों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही। सरकार गंभीर नहीं है। विपक्ष में गौ वंश के नाम पर राजनीति की। अब सरकार आने पर भी रक्षा नहीं कर पा रहे। आवश्यकता होने पर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन के लिए तैयार है।

वन विभाग के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

धरना स्थल पर ही मनाया कृष्ण जन्मोत्सव

रायपुर। वन विभाग के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 16वां दिन है। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों का आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी धरना जारी है। इस दौरान कर्मचारी धरना स्थल पर ही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर भगवान कृष्ण से भजन-कीर्तन करते हुए मनोकामना की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल में ही मटकी फोड़ का आयोजन किया, जिसमें महिला-पुरुष सभी ने मटकी फोड़ी। वहीं भजन मंडली के कृष्ण भजन, छोहर गीत में हजारों कर्मचारी झूमते नज़र आए।

धरने की अगुवाई कर रहे प्रांताध्यक्ष राम कुमार सिन्हा ने बताया कि कर्मचारी नियमितीकरण, स्थायीकरण और आकस्मिक निधि सेवा लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उनके नौ सूत्री मांग पत्र में सीधी भर्ती पर रोक लगाने, रिक्त स्थानों पर दैनिक वेतनभोगियों का समायोजन, 8-9 माह का वेतन भुगतान और श्रमिक सम्मान राशि के 4 हजार रुपये का तत्काल भुगतान करने की मांग शामिल है। इसके अलावा, समान काम के लिए समान वेतन भुगतान की भी मांग की गई है।

राम कुमार सिन्हा ने नियमों के उल्लंघन पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि डिपो में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है।

प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंपा महादेव सट्टा एप का मामला

■ **गृहमंत्री विजय शर्मा बोले- विदेश से भी भारत लाए जाएंगे आरोपी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा एप का मामला सीबीआई को सौंपा है। महादेव सट्टा एप को लेकर कुल 70 केस दर्ज हैं। इन सारे प्रकरण सीबीआई को सौंपा गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, 70 केस महादेव एप के संदर्भ में दर्ज थे। ईओडब्ल्यू में भी केस था। एक से बढ़कर अनेक प्रदेशों का ये मामला है। कुछ मुख्य आरोपी विदेश में भी है, ऐसी जानकारी है। सारे विषयों को देखते हुए सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और कठोरता के साथ इस पर कार्रवाई होगी। विदेशों में भी जो लोग है उनको भी भारत लाया जाएगा। बता दें कि इस मामले में अब तक ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईडी करीब 16 महीने से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंडिकेट

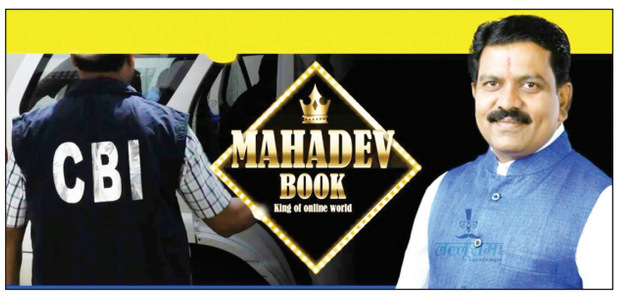

को संरक्षण देने वालों में उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं। ईडी के अनुसार, इस मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था। ईडी, ईओडब्ल्यू के अलावा महादेव ऐप केस में सेबी भी जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसकी जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कर रही है।

महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक रायपुर की अदालत में तीन अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दायर की है। इस मामले में ईडी ने राज्य में पहले भी कई छापे मारे हैं। ईडी ने पहले भी कहा है कि महादेव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है। छत्तीसगढ़ से ऐप के दो मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल आते हैं। इस मामले में ईडी ने अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

क्या है महादेव सट्टा ऐप ?

महादेव सट्टा ऐप सट्टे के लिए बनाया गया है। इस पर यूजर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम नाम के लाइव गेम खेलते हैं। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खोले गए।

बिलासपुर-मुंबई और बिलासपुर-हैदराबाद फ्लाइट हो सकती है शुरू

रायपुर। न्यायधानी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि जल्द ही बिलासपुर से मुंबई और हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एलाइंस एयर कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली है। इसके लिए कराए गए सर्वे में भी कंपनी को मुंबई और हैदराबाद के लिए काफी संख्या में यात्री मिलने की उम्मीद है। एलाइंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से संचालित सभी हवाई सेवा को मिल रहे अच्छे प्रतिसाद से उत्साहित होकर बिलासपुर से मुंबई और हैदराबाद मार्ग पर नई उड़ान प्रारंभ करने की संभावना को टटोला गया था। उक्त रूट में पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने की पूरी संभवाना है। इसलिए एलाइंस एयर कंपनी के द्वारा किए गए आकलन में मुंबई से जलगांव चल रही उड़ान को बिलासपुर तक बढ़ाने और हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर उड़ान के रायपुर स्टॉपेज समाप्त हो जाने के कारण उसे बिलासपुर लाने के बारे में अच्छी रिपोर्ट आई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने उक्त संबंध में मीडिया को बताया कि एलाइंस एयर कंपनी द्वारा रायपुर में अपना सेटअप पूरी तरह समाप्त कर लिया है। इसके बाद जो उड़ान हैदराबाद से जगदलपुर होकर रायपुर तक चल रही थी।

प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के मायने

प्रो सतीश

भारत बुद्ध और गांधी की धरती है। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध में कई पेंच हैं। इसमें अनेक पक्ष हैं, जिनके निहित स्वार्थ हैं। जब तक उनकी मंशा साफ नहीं होगी, शांति बहाली मुश्किल है। दुनिया को मालूम है कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ और किसका दोष ज्यादा है। क्या अमेरिका के निहित स्वार्थ को समझे बिना युद्ध थम जायेगा? भारत अमेरिका के साथ-साथ रूस का भी मित्र है। भारत किसी भी शक्ति के प्रभाव में अपनी सोच और नीति से समझौते के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐतिहासिक है। कूटनीतिक नजरिये से भी इसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने युद्ध में मारे गये बच्चों के बारे में जानकर कहा कि किसी भी सभ्य समाज में घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तटस्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले बड़ा सवाल यह था कि क्या यह पिछले महीने उनकी मास्को यात्रा पर पश्चिमी देशों की नाराजगी के बाद भू-राजनीतिक क्षति नियंत्रण की कवायद है और क्या यह भारत के पश्चिमी साझेदारों को संदेश है कि भारत रूस के पक्ष में नहीं है। अब जब यह यात्रा समाप्त हो चुकी है, यह अधिक प्रासंगिक प्रश्न प्रतीत होता है कि क्या इस यात्रा ने मास्को को कोई संदेश दिया है। रूस और भारत के रक्षा सहयोग के बारे में सभी जानते हैं। पर यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग की दिशा में पहल का उल्लेख आश्चर्यजनक था। यह संभव है कि इससे रूस में भौहें चढ़ गयी हों। यह पहलू और ध्यान देने योग्य हो गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में थे, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में थे और दो नये समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले रूस का दौरा किया था और इसलिए वैश्विक मीडिया की नजरें उनकी यूक्रेन यात्रा पर टिकी हुई थीं। उनके इस दौरे को बीबीसी ने 'कूटनीतिक संतुलन का परीक्षण' बताया। विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का चित्रण जिस रूप में भी करे, पर कुछ बातें स्पष्ट हैं। पहला, युद्ध केवल भारत के कहने से नहीं रुकेगा। युद्ध केवल यूरोप में ही नहीं है, बल्कि मध्य-पूर्व एशिया में भी चल रहा है। ताइवान और दक्षिण चीन समुद्र के मुहाने पर युद्ध की स्थिति बन रही है। दुनिया के सभी महत्वपूर्ण देश इन तीनो संघर्षों में शामिल हैं। भारत की बात कौन सुनेगा! न तो चीन से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है और न ही अमेरिका से, जिसकी भूमिका बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम में संदिग्ध रही है। अमेरिका के अपने निहित स्वार्थ हैं। युद्ध के जरिये वह यूरोप को नाटो के मजबूत धागे से बांधकर रखना चाहता है, जिससे वह महाशक्ति बना रहे। चीन अपना वजूद मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी ताकत को चुनौती देता रहा है। क्या ये दोनों देश भारत की सलाह मानने के लिए तैयार होंगे? दूसरा, विश्व पुन: दो भागों में विभाजित होता दिख रहा है। एक तरफ अधिनायकवादी राजनीतिक शक्तियों वाले देश हैं, जिनमें रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को एक साथ देखा जा सकता है। लैटिन अमेरिका के कुछ देश भी इसमें शामिल हो सकते है। दूसरी तरफ नाटो से जुड़े हुए देश हैं, जिनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। तीसरा खेमा तटस्थ देशों का है, जिसमें भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ के इन देशों की अपनी दरकार है। वे शांति के पक्ष में हैं। वे मजबूत अंतरराष्ट्रीय संगठन की गुहार भी लगा रहे रहे हैं, जो युद्ध की विभीषिका को रोक सके। पर यह ढांचा बनाने में समय लगेगा। तीसरा, यूरोप की मानसिकता एक-दूसरे के विरोध में बनकर तैयार हुई है। अंधकार युग के बाद राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति एक-दूसरे के विरोध में हुई थी। उपनिवेशवाद ने इसे और हवा दिया। एंग्लो-फ्रेंच युद्ध उसी का नतीजा था। रूस में कम्युनिस्ट क्रांति ने जले पर नमक का काम किया। लेनिन की आम सहमति वाला संघ स्टालिन काल में बदल गया। पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों के पैर जकड़ दिये गये। साल 1990 के बाद के परिवर्तन ने आपसी नफरत को कम नहीं किया। इसलिए शांति की बात इन देशों में अंग्रेज भू-राजनीतिक विद्वान मैकिंडर के सिद्धांत पर चलती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पूर्वी यूरोप को कब्जे में लेगा, वह मुख्य भूमि का मालिक होगा और जो मुख्य भूमि का मालिक होगा, वह दुनिया पर राज करेगा।

मोदी का तीसरा कार्यकाल और तीन 'सी' का जाल

शेखर गुप्ता

सी से शुरू होने वाला एक शब्द सेंसस यानी जनगणना अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों का विषय बन गया है, जबकि इसे एक आम विषय होना चाहिए था। जैसा कि हम जानते हैं यह समय भी हमारे राजनीतिक इतिहास का आम समय नहीं है। पिछले दशक में कई पुराने नियम नए सिरे से तैयार हुए, कुछ नियम दफन हुए और कई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

उनमें से एक है हर दशक होने वाली जनगणना। यह खबर आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार आखिरकार लंबे समय से टली आ रही जनगणना कराने वाली है जिसे 2021 में होना था। ऐसे में यह सही वक्त है जब हमें उन तीन बड़ी हकीकतों का सामना करना है जिनका प्रतिनिधित्व तीन 'सी' करते हैं यानी- कास्ट, सेंसर और कॉन्स्टिट्यूशन यानी जाति, जनगणना और संविधान। अगर यह सरकार मोदी 3.0 है तो हम इसे 3सी का जाल कह सकते हैं। इसके महत्त्व का पहला संकेत यह है कि आखिरकार जनगणना कराने की योजना बनी है।

एक दशक तक मोदी सरकार इन तीनों से मनचाहे ढंग से निपट रही थी। हिंदी प्रदेशों की जाति आधारित पार्टियों को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया गया और नरेंद्र मोदी के उभार को पिछड़ी और छोटी जातियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया गया।

भाजपा ने बड़ी संख्या में पिछड़े नेताओं को टिकट दिया, एक पिछड़े नेता को प्रधानमंत्री बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया और उसके बाद एक आदिवासी को भी। कांग्रेस ने कभी देश के गैर कुलीन तबकों को इतना व्यापक और अधिकारसंपन्न प्रतिनिधित्व नहीं दिया, एक दशक में तो कतई नहीं। मोदी युग की भाजपा ने जाति और निचले वर्ग के मुद्दों को बहुत सावधानीपूर्वक समेट दिया था। वह मोदी युग अब समाप्त नजर आ रहा है।

जाति की वापसी को समझने के लिए सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के मुद्दे पर दोहरी तेजी से वापसी को देखा जा सकता है। बीते पांच सालों में इसी तरीके से 63 अधिकारियों को नियुक्त किया गया और अगर कोई विरोध हुआ भी तो उसकी अनदेखी कर दी गई। इस बार विपक्षी नेताओं खासकर राहुल गांधी के कुछ ट्वीट के

के बाद हड़बड़ाहट में इसे वापस ले लिया गया। बीती गर्मियों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पार्टी को जो झटका लगा है उससे भाजपा के थिंक टैंक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसकी हार के लिए मोटे तौर पर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के गठबंधन और मुस्लिमों का साथ आना जिम्मेदार है। मुस्लिमों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर सकती है और न ही करेगी।

आपने देखा ही होगा कैसे भाजपा के प्रमुख नेता और खासकर उसके मुख्यमंत्री उन पर अत्यधिक आक्रामक ढंग से हमला बोलते हैं। वे ऐसा इस उम्मीद में करते हैं कि हिंदू उनके पास एकजुट हो जाएंगे। पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि विपक्षी दल इस धारणा को मजबूत करें कि भाजपा और हिंदुत्ववादी ताकतें उच्च वर्ग के कुलीनों को मदद पहुंचाती हैं, न कि सभी हिंदुओं को। सीधी भर्ती दोबारा शुरू होगी लेकिन इस बार उसमें पहले से तय कोटा होगा। इससे उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा।

अतीत में कांग्रेस तथा गैर भाजपा गठबंधन सरकारों, यहां तक कि जनता पार्टी की सरकारों ने अपनी मर्जी से लोग चुने थे जो अब संभव नहीं। अब तो यह भी संभव नहीं होता कि बाहर से वित्त सचिव लाया जा सके जबकि पी वी नरसिंह राव की अल्पमत सरकार ने मोंटेक सिंह आहलूवालिया के रूप में बाहर से वित्त सचिव चुना था। यही कारण है कि हमें जनगणना में होने वाली प्रगति पर करीबी नजर रखनी होगी।

हमारी दशकीय जनगणना 1881 में आरंभ हुई थी। उसके बाद 1941 में विश्व युद्ध के चलते यह नहीं हुई, वरना हर दशक पर इसे अंजाम दिया गया। 2021 में कोविड महामारी ने इसे बाधित किया। सच तो यह है कि कोविड के आने के पहले भी जनगणना को लेकर कोई सक्रियता नहीं नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि मोदी सरकार अपना समय लेगी। इन आम चुनावों से 10 महीने पहले सरकार ने नए जनगणना भवन का धूमधाम से उद्घाटन किया। परंतु उस समय तक भी जनगणना को लेकर कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था।

माना जा रहा था कि भाजपा ब्रिटिश युग की दशकीय जनगणना को लेकर बाध्य महसूस नहीं कर रही। वह इसके लिए सही समय का इंतजार कर सकती थी। सही समय से तात्पर्य संसदीय क्षेत्रों के नए परिसीमन की अगली समय सीमा भी हो सकता था।

इसे ठीक से समझते हैं। परिसीमन को विभाजनकारी विषय माना जाता रहा है क्योंकि राज्यों की आबादी में इजाफे में बहुत भिन्नता है। खासकर तटवर्ती, आर्थिक और सामाजिक रूप से अग्रणी एवं हिंदी प्रदेशों की आबादी में बहुत अंतर है। परिसीमन के परिणामस्वरूप संसदीय सीट में उच्च जन्म दर वाले राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी जबकि जनसंख्या नियंत्रण करने वालों की कम होगी। इससे अस्थिरता और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता पैदा हो सकती है।

यही वजह है कि एक के बाद एक सरकारें इसे टालती रहीं। 2001 में आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक संविधान संशोधन लाकर परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसे इस अवधि के बाद यानी 2026 के बाद होने वाली जनगणना पर आधारित होना था। संभव है भाजपा इस बात की प्रतीक्षा कर रही हो कि वह तीसरी बार बहुमत पाने और चौथे की ओर बढ़ने के बाद इस दिशा में बढ़ेगी लेकिन 4 जून को ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक रूप से विवादित परिसीमन को अंजाम देना विकल्प नहीं रहा। ऐसे में जनगणना को अनंतकाल तक टालने और संसद में शर्मिंदा होने का कोई अर्थ नहीं था।

संसद के पिछले सत्र में राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इसी संसद के तहत जाति जनगणना हो। उधर भाजपा, लंबे समय से लंबित 2021 की जनगणना तक की बात नहीं कर रही थी। अब ऐसा करना राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह गया था। अगर जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम भी हो तो चकित होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जरूर चौंकूंगा। यह राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के हाथों हार जैसा होगा।

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उस स्थिति में विपक्ष के मुख्य हथियारों में से एक बेकार हो जाएगा। बाद के दोनों 'सी' पहले से जुड़े हैं। जाति की अनिवार्यता ने ही लैटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के मामले में भाजपा के साझेदारों को सतर्क किया।

उदाहरण के लिए बिहार के दो साझेदार दलों की बात करें तो अगर उनके समर्थन वाली केंद्र सरकार आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करती है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे की शिव सेना खामोश हो सकती है लेकिन लोक सभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद वे बहुत परेशान हैं।

आखिर में संविधान। प्रधानमंत्री इस हकीकत को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने लोक सभा के गठन के अवसर पर संविधान के सामने सर झुकाया। चुनाव प्रचार तक दावे किए जा रहे थे कि एक बार 400 सीट का आंकड़ा पार करने के बाद संविधान में बड़े संशोधन किए जा सकते हैं। अन्य लोगों के अलावा अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी ने भी इस विषय में बयानबाजी की थी।

इस बात को लेकर भी बहस थी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के 13 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे की व्याख्या और उसे छेड़छाड़ से परे बताने वाला आदेश अभी भी प्रासंगिक है या नहीं। वंचित जातियों और वर्गों के बीच इसे आरक्षण पर हमले के रूप में देखा गया। विपक्ष ने भी इसे फैलाने में पूरा जोर लगाया। इसके फलस्वरूप संविधान को अब ऐसा दर्जा दे दिया गया है जैसा इससे पहले कभी नहीं था। जबकि अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में निरंतर बदलाव के बीच इसमें भी समय-समय पर संशोधन की जरूरत होती है। अब तक इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं।

इन संशोधनों का इतिहास बताता है कि इनमें से ज्यादातर व्यापक सहमति से किए गए जहां विपक्षी दल भी साथ थे। क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा करना चाहेगी? बिना सर्वसम्मति के वह संविधान को हाथ लगाने से डरेगी। आखिरी बात, ये तीनों 'सी' मिलकर भाजपा को एक चौथे 'सी' की ओर ले जाएंगे- आम सहमति। अगर वह उसे नहीं अपनाएगी तो यह सरकार के लिए एक झटका होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-4)

यहां तक उस दल की दुस्साहसपूर्ण नीति का परदा फाश किया है जो कि अन्ध अविश्वास की दलदल में आशिरोमग्न होकर वेदों का भी सफाया करने पर तुला है। परन्तु इसके अतिरिक्त एक दूसरा दल भी महा भयानक है जो कि अन्ध-विश्वास के कारण एक अक्षर को भी प्रक्षिप्त मानने के लिये तैयार नहीं। हम इसे महा भयानक इसलिये कह रहे हैं कि जिस प्रकार आर्यसमाज आदि अन्ध-अविश्वास के कारण ग्रन्थों के रूप को बिगाड़ रहे हैं, इसी प्रकार कुछ सनातन धर्मी भी अन्धविश्वास के कारण प्रत्येक पाठ के समर्थन की धुन में आकाश पाताल को एक करने में कोर कसर नहीं रखते। हम अन्ध-विश्वास और अन्ध-अविश्वास दोनों को बराबर समझते हैं, तथा प्रक्षिप्त मान कर किसी अंश कौं निकाल देना उतना ही अपराध समझते हैं जितना कि अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये प्रक्षिप्त मिला देने में समझा जा सकता है। हम तो इसलिये निस्सङ्कोच भाव से यह कह सकते हैं कि पुराणों में प्रक्षिप्त है और अवश्य है, परन्तु उसके एक भी अक्षर को निकाल डालने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। कुछ दिन से लोगों में भले ही यह धारणा परिपक्व हो जाये कि प्रक्षिप्त किसी हेय, अनुपादेय, एवं दूरतस्त्याज्य वस्तु का नामान्तर है परन्तु वास्तव में- मूल ग्रन्थ के रचयिता से भिन्न व्यक्त्यन्तरनिर्मित% ही इसका अर्थ हो सकता है। वेदों को छोड़ कर अन्य किसी भी ग्रन्थ में यदि ऐसे पाठ की सम्भावना हो तो उसकी हेयोपादेयता की व्यवस्था वेद-मूलकता पर निर्भर है। कोई प्रक्षिप्त अंश केवल इसलिये ही त्याज्य नहीं हो सकता कि वह व्यक्त्यन्तर-निमित है और नांही स्मृति पुराण आदि किसी ग्रन्थ- विशेष का मूलपाठ केवल इसलिये ग्राह्य हो सकता है क्योंकि वह मूल-ग्रन्थ-निर्माता की कृति है। इस प्रकार के विचार ग्रन्थ-निर्माता के विषय में श्रद्धातिरेक के परिचायक भले ही हो सकते हों, परन्तु धर्माधर्म के निर्णय में निर्माता के बजाय वेदमूलकता हो कसौटी होनी चाहिये। (**क्रमश**)

अमेरिका के कॉन्सर्ट में मुकेश ने ली थी आखिरी सांस

अनन्या मिश्रा

आज के दिन यानी की 27 अगस्त को हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मुकेश ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। आज भी वह अपने गाए हुए गानों से लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मुकेश की आवाज का जादू देश-विदेश तक में फैला था। भले ही वह आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन उनके द्वारा गाए गए गानों को आज भी लोग गुनगुनाते हैं।

हिंदी सिनेमा में गुजरे हुए जमाने के गायकों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह गायक अपने बेहतरीन और सदाबहार गानों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन आज हम इस आर्टिकल के जरिए जिस गायक की बात कर रहे हैं, वह अभिनेता राज कपूर की आवाज कहे जाते थे। मुकेश की फैन फॉलोइंग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। उनकी आवाज को विदेशों में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। मुकेश ने दोस्त-दोस्त न रहा, जीना यहां मरना यहां, कहता है जोकर, आवारा हूं जैसे कई सुपरहिट गाने गाए हैं। लोगों को इस बात की खुशी रही कि मुकेश अपने आखिरी समय में भी अपना पसंदीदा गाना गाते हुए इस दुनिया को छोड़कर गए।

बता दें कि 22 जुलाई 1923 में जन्मे मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। इनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। उन्हें बचपन से ही गाने का काफी ज्यादा शौक था। वह अपने क्लास के साथियों को भी अक्सर गाना गाकर सुनाया करते थे। हालांकि 10वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पीडब्लूडी में नौकरी करने लगे। लेकिन मुकेश का मन नौकरी में नहीं लगता था। क्योंकि वह हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहते थे।

एक बार मुकेश अपने किसी रिश्तेदार मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे। इस दौरान उनके रिश्तेदार को मुकेश की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई कि वह उनको लेकर मुंबई आ गए। यहां पर मोतीलाल ने मुकेश को गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। जिसके बाद साल 1941 में मुकेश को फिल्म निर्दोष में अभिनय का मौका मिला। साथ ही इस फिल्म के सभी गाने भी उन्होंने गाए। इसके बाद मुकेश ने आह, अनुराग, माशूका और दुल्हन जैसी फिल्मों में भी बतौर एक्टर अभिनय किया।

मुकेश और राज कपूर में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी। मुश्किल समय में दोनों एक-दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। वहीं साल 1959 में राज कपूर को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया। तो वहीं राज कपूर के जिगरी दोस्त मुकेश को भी फिल्म अनाड़ी के सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्ले बैक सिंगर का फिल्म फेयर अवॉर्ड मिला था। मुकेश ने अपने 40 साल के लंबे फिल्मी कॅरियर में करीब 200 से अधिक फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उस दौरान वह हर सुपरस्टार की आवाज बन गए थे।

पाकिस्तान की आई.एस.आई. का दोहरा खेल

भूपिंदर सिंह

जासूसी उपन्यासकार जॉन ले कैरे जासूसों को जटिल और एकाकी प्राणी बताते हैं, जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। इस तरह का एकांत उन्हें धोखा देने, साजिश करने और एकतरफा महत्वाकांक्षा रखने के लिए मजबूर करता है। तथ्य यह है कि वे गहरे और अंधेरे रहस्यों को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनसे संयम से काम लेने की उम्मीद की जाती है। कभी-कभी उन्हें अपने 'विशेषाधिकार' (पढ़ें, गोपनीय जानकारी) को लापरवाह उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि वे बहुत सारी गंदगी से खतरनाक रूप से अवगत होते हैं, इसलिए वे अपनी महत्वाकांक्षा से डरते हैं।

कहावत है कि सीजर की पत्नी की तरह, हमेशा संदेह से परे होना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज-इंटैलीजेंस (आई.एस.आई.) अपने पेशेवर दायरे से बाहर जाकर घरेलू राजनीति, वाणिज्यिक हितों या यहां तक कि अपने स्वीकृत जनादेश से परे सीमा पार की हरकतों में शामिल होने के लिए बदनाम है। अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असली ताकत है (इसके बावजूद सिविल राजनेताओं का दिखावा), तो यकीनन दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डी.जी.-आई.एस.आई.है। सेना प्रमुख या प्रधानमंत्री के प्रति कथित वफादारी (ऐसे समय में जब सेना पीछे हट जाती है और राजनेताओं का दबदबा होता है) अंतर्निहित है, हालांकि, पाकिस्तानी आख्यान में, पीठ में छुरा घोंपना आम बात है। विडंबना यह है कि इतने शक्तिशाली 'नंबर 2' पद के लिए, अब तक 29 डी.जी.-आई.एस.आई.रहे हैं, और केवल एक ही सेना प्रमुख के पद पर चढ़े हैं, यानी वर्तमान सेना प्रमुख, जनरल असीम मुनीर। यहां तक कि वर्तमान सेना प्रमुख, जनरल असीम मुनीर

को भी अचानक डी.जी.-आई.एस.आई. के पद से हटा दिया गया था क्योंकि तत्कालीन पी.एम. इमरान खान उनके आचरण से असहज महसूस कर रहे थे (बाद में कर्म ने समीकरण को बराबर कर दिया क्योंकि इमरान आज खुद जेल में हैं)।

ऐसा लगता है कि यह प्रोफाइल एक वफादार, निर्विवाद और कमजोर डी.जी.-आई.एस.आई. की है, जो गुमनामी से संतुष्ट होकर काम करता है (अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए) और बिना किसी उपद्रव के सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी रूप से सूर्यास्त की ओर बढ़ता है। अवसर, लालच और पहुंच को देखते हुए, कई लोग अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। एक डी.जी.-आई.एस.आई. का एक दिलचस्प मामला है, जो सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त तो हुआ, लेकिन उसका कार्यकाल केवल कुछ घंटों का था और आधिकारिक रिकॉर्ड में यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनने के रूप में दर्ज नहीं है। लैफ्टिनैंट जनरल जियाउद्दीन बट एक विशिष्ट डी.जी.-आई.एस.आई. थे, जो बातचीत करने के लिए तालिबान के खूंखार नेता मुल्ला उमर से मिलने के लिए अफगान सीमा पार गए थे । वे पाकिस्तानी राज्य के अंधेरे गलियारों और चालों के बीच में थे। जियाउद्दीन की दूसरे प्रतिस्पर्धी सत्ता केंद्र यानी पी.एम. नवाज़ शरीफ़ तक सीधी पहुंच थी, और वह सेना प्रमुख के पद से परवेज मुशर्रफ को हटाने के शरीफ के प्रयास में एक इच्छुक सहयोगी था।

तख्तापलट (या मुशर्रफ इसे जवाबी तख्तापलट कहते हैं) से पहले, 'जनरल' जियाउद्दीन को जल्दबाजी में सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था और फिर पाकिस्तानी सेना ने तुरंत उन्हें हटा दिया, जिसने अपने डी.जी.-आई.एस.आई. की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने से इंकार कर दिया था। जासूस मास्टर की चाल विफल हो गई। जियाउद्दीन संवैधानिक रूप से उचित से परे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखने वाले डी.जी.-आई.एस.आई. में से पहले या आखिरी नहीं थे। एक और व्यक्ति जो संविधान से परे महत्वाकांक्षा रखने और उसकी कीमत चुकाने के लिए चर्चा में है, वह पूर्व डी.जी.-आई.एस.आई., लैफ्टिनैंट जनरल फैज हमीद हैं। हाल ही में पाकिस्तानी 'प्रतिष्ठान' (जिसका नेतृत्व क्रमशः पूर्व और वर्तमान सेना प्रमुख कमर बाजवा और असीम मुनीर कर रहे हैं) और इमरान खान सरकार के बीच छिड़े विवाद के बीच अपनी संदिग्ध भूमिका के कारण समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किए जाने के बाद, उन्हें अपने तत्कालीन शक्तिशाली पद का दुरुपयोग करने और कुछ रियल्टी सौदे में लोगों को मजबूर करने के कारण फिर से सार्वजनिक समाचारों में लाया गया है।

जबकि उन्हें पहले अपेक्षाकृत रूप से सम्मान बचाने के लिए 'समय से पहले सेवानिवृत्ति' दी गई थी (हालांकि हर कोई बेहतर जानता था), उन्हें अपदस्थ इमरान खान सरकार (जिसके बारे में माना जाता है कि लैफ्टिनैंट जनरल फैज हमीद की पहचान इसी से है) के खिलाफ नए अंक हासिल करने के लिए शर्मनाक तरीके से कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। लैफ्टिनैंट जनरल फैज हमीद के कई कृत्यों से यह पता चलता है कि वे बहुत अहंकारी, घमंडी और अतिशयोक्तिपूर्ण आचरण करते थे जो जासूसों की भूमिका के अनुकूल नहीं था, लेकिन शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उन पर हावी हो गई थी। जैसे-जैसे पासा पलटा, कहानी बदल गई और इसके साथ ही उन्हें भी हटा दिया गया। अगर मौजूदा सरकार अपनी राह पर चलती रही तो वे बदनामी और बदनामी के दूसरे दौर के लिए वापस आ सकते हैं।

आज का इतिहास

1922 तुर्की की सेनाओं ने ग्रेको-तुर्की युद्ध के दौरान अफोकेन को, उनके मुठभेड़ की पहली जीत पर फिर से कब्जा कर लिया।

1927 पांच कनाडाई महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट कनाडा से पूछने के लिए एक याचिका दायर की, ब्रिटिश नॉर्थअमेरिका अधिनियम, 1867 की धारा 24 में पर्सन्स शब्द महिला व्यक्तियों को शामिल करता है, जिस पर विनम्रतापूर्वक जवाब दिया गया कि यह नहीं है।

1928 साठ से अधिक राष्ट्रों ने राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में त्याग करते हुए केलॉग-ब्रींड पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।

1939 जेट ईंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी।

1955 नॉरिस और रॉस मैक्किटर की %गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली बार प्रकाशित हुई है और तुरंत सफल हुई है। पुस्तक मूल रूप से गिनीज ब्रेवरी के स्वामित्व में थी और वर्तमान में जिम पैटीसन ग्रुप की संपत्ति है, जो उसी कंपनी की है जो रिप्ले एंटरटेनमेंट, इंक।

1957 मलाया का संविधान लागू हुआ, तीन दिनों के लिए मलाया के महासंघ ने यूनाइटेडकेटरडे से औपचारिक स्वतंत्रता हासिल की।

1962 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से मेरिनर 2 अंतरिक्ष जांच शुरू की गई है।

1967 ईस्ट कोस्ट रेसलिंग एसोसिएशन की स्थापना की गयी।

1979 दो अलग-अलग हमलों में, आईआरए बमों ने 18 ब्रिटिश सैनिक वॉरेनपॉइंट, उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटिश एडमिरल लुईमाउंटबेटन और तीन अन्य को काउंटी स्लीगो, आयरलैंड में मार दिया।

1990 वाशिंगटन स्थित इराकी दूतावास के 55 में से 36 कर्मचारियों को अमेरिका ने निष्कासित कर दिया।

1991 सोवियत संघ के विघटन-मोल्दोवा ने सोवियत तख्तापलट के प्रयास की विफलता के बाद अपनी निर्भरता की घोषणा की।

1992 राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत स्वीकृत नो फ्लाई ज़ोन को अधिसूचित किया है।

2000 मॉस्को के ओस्टैंकिनो टॉवर में आग लग गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और शहर के चारों ओर टेलीविजन और रेडियो सिग्नल खराब हो गए।

लेटरल एंट्री पर कांग्रेस और इंडी ठगबंधन का फेक नैरेटिव

प्रेम शुक्ल

आज कल आप 'लेटरल एंट्री' के बारे में इधर-उधर चर्चा सुन रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस सहित इंडी ठगबंधन के घटक दलों की ओर से आदतन इस विषय पर भी देश और जनता को गुमराह करने की एक निचले स्तर की साजिश रची जा रही है। फिर इस तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार ही आरक्षण से बचने के लिए 'लेटरल एंट्री' की स्कीम को लेकर आई थी और वही अब आरक्षण देने के लिए अपनी ही स्कीम से पीछे हट रही है। इस तरह की बातें एकदम से मोदी सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं जिसे विपक्षी इंडी ठगबंधन हवा दे रहा है।

एंटी-मोदी और एंटी-इंडिया सेक्शन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जनता को बरगलाने के लिए सारी नापाक चालें चल कर देख ली लेकिन वे जनता के दिलों से नरेन्द्र मोदी को जब हटा नहीं पाए तो अब वे आरक्षण पर पेपर-डिजाइंड 'फेक नैरेटिव' की एक सीरीज तैयार कर के आए हैं जिसका उदाहरण हमने लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, एससी-एसटी क्रीमी लेयर से संबंधित विषय पर सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद भी देखा और अब 'लेटरल एंट्री' वाले विषय में भी देख रहे हैं। जिन पार्टियों का इतिहास ही जातिगत राजनीति और आरक्षण के खिलाफ रहा है, आज वे इसके सबसे बड़े पैरोकार बनने का झूठा दंभ भर रहे हैं जबकि उनकी असली मंशा कुछ और ही है!

जहां तक लेटरल एंट्री का विषय है, ये कंसेप्ट तो कांग्रेस की यूपीए सरकार लेकर आई थी जिसमें वे सभी दल भी सहभागी थे जो आज कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दौर में लैटरल एंट्री सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बिलकुल भी नहीं थी और इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया।

हालांकि, लेटरल एंट्री का पहला और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें आजादी के ठीक बाद पंडित नेहरू की सरकार में ही दिख गया था जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित को चार-चार देशों में भारत का राजदूत बनाया जबकि उन्होंने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 1971 में लेटरल एंट्री के जरिए ही आर्थिक सलाहकार बनाए गए थे। बाद में वे वित्त मंत्री और पीएम भी बने। मंतोष सोढ़ी, सैम पित्रोदा, वी कृष्णमूर्ति, बिमल जालान, कौशिक बसु, केपीपी नांबियार, अरुणा मैरा, आईजी पटेल, अरविंद विरमानी जैसे लोगों को भी लेटरल एंट्री के जरिये ही सरकार का हिस्सा बनाया गया था। यहां तक कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी योग्यता के सोनिया गांधी को लेटरल एंट्री की तर्ज पर ही यूपीए सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) का अध्यक्ष बना कर प्रधानमंत्री के ऊपर बिठा दिया गया था।

यहां तक कि कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के दौरान गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसने यूपीए के दस वर्षों के दौरान शासन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसमें भी कई लैटरल एंट्री थीं और उन सभी में एससी, एसटी और ओबीसी को अनदेखा किया गया।

एनएसी के सदस्यों में से एक जीन ड्रेज़ थे, जिन्हें हाल ही में दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते देखा गया था। पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर भी एनएसी का हिस्सा थे। इसी तरह मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नंदन नीलेकणि और अन्य जैसे अन्य हाई प्रोफाइल लैटरल एंट्री को बिना किसी व्यवस्थागत प्रक्रिया के लिया गया। 2018 में मोदी सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से लैटरल एंट्री को संस्थागत रूप दिया, जिससे प्रक्रिया में अपारदर्शिता दूर हुई और सिस्टम में तदर्थ प्रविष्टियों पर रोक लगी।

वास्तव में, यह कांग्रेस ही है जिसने जामिया मिलिया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान बताकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के अधिकारों का हनन किया। वास्तव में, यह कांग्रेस ही है जिसने अपनी राज्य सरकारों में एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का हनन करने की साजिश रची। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके उदाहरण हैं।

कांग्रेस शुरुआत से ही आरक्षण के खिलाफ है। नेहरू जी कहते थे कि अगर एससी/एसटी, ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती, तो वो प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते और आज यहां पहुंचते। 27 जून 1961 को पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने 1951 में जाति जनगणना का भी विरोध किया था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इंदिरा गांधी कहती थी - न जात पर, न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोक सभा में 6 सितंबर 1990 को अपने भाषण के दौरान मंडल कमीशन पर अपनी बात रखते हुए आरक्षण का विरोध किया था।

इससे पहले 1985 में भी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में आरक्षण के खिलाफ बोला था। कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का निर्णय वर्षों तक लटका कर रखा। सपा की सरकार ने अध्यादेश लाकर यूपी में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है। 1990 से 2005 के दौरान 15 साल तक बिहार में राजद की लालू-राबड़ी सरकार थी लेकिन इन 15 वर्षों में अतिपिछड़ों के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

नरेन्द्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री पारदर्शी, संस्थागत तरीके से की जाएं जो सामाजिक न्याय और आरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप हों। मोदी सरकार सामाजिक न्याय प्रदान करने में सबसे आगे रही है, उसी के मद्देनजर सरकार परिपत्र को फिर से संशोधित कर रही है। लेटरल एंट्री को अब तक एकल-संवर्ग पदों के रूप में नामित किया गया था और इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार अब इस कमी को भी संशोधित कर रही है और न केवल लेटरल एंट्री को एक संस्थागत प्रक्रिया बनाकर बल्कि इसमें संशोधन कर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी सुनिश्चित कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो सरकार में आने के साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में निरंतर काम करते रहे हैं ताकि समाज के पिछले पायदान पर पहुंचे लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल हों। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, सरकारी सेवा में कार्यरत एससी एवं एसटी की प्रोन्नति का मामला हो, लोकसभा एवं विधानसभा में उनके आरक्षण की अवधि बढ़ाने का मामला हो, एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को मानने में असमर्थता जाहिर करना हो, स्टार्ट-अप इंडिया व स्टैंड अप इंडिया योजनाओं में दलितों-पिछड़ों को आगे बढ़ाना हो, मुद्रा योजना में ऐसे वर्गों को आगे बढ़ाना हो या सरकार की हर योजना में ऐसे वर्गों का विशेष ख़याल रखना हो - मोदी सरकार ने हमेशा एक कदम आगे बढाते हुए बाबा साहेब के सपनों को मूर्त रूप में धरातल पर उतारा है।

आरक्षण प्रणाली का उपयोग चुनावी आवश्यकताओं के लिए होता है

अनुभा मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एस.सी. श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। समय-समय पर राजनीतिक विद्वानों ने जातिगत स्तर पर सबसे निचले तबके को लाभ पहुंचाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आरक्षण की प्रभावशीलता के बारे में बहस की है। मामले पर नियंत्रण रखने के लिए, संवैधानिक निर्माताओं ने राष्ट्रपति को (अनुच्छेद 341 में)एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अस्पृश्यता के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित 'जातियों-नस्लों या जनजातियों' को एस.सी. के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। अनुसूचित जाति समूहों को संयुक्त रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एस.सी. सूची में कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यों ने इन समूहों को अधिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है, लेकिन यह मुद्दा न्यायिक जांच में चला गया है और इस फैसले के साथ एस.सी. ने समाज के कुछ वर्गों तक पहुंचने के लिए जातियों जनजातियों नस्लों को उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखा है जो अन्यथा क्रीमीलेयर पहले से ही ऐसे प्रावधानों का लाभ उठा रहा है जिसके कारण यह संकट में पड़ जाता है। वर्तमान आरक्षण नीति के साथ समस्या यह है कि ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण योजना से अवसर मिल रहे हैं और लाभ हो रहा है जबकि गरीब पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण प्रणाली इतनी भ्रष्ट है और इसका उपयोग चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकारात्मक तरीके से किया जाता है कि यह दलितों और उन लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के अपने वास्तविक प्रचार को पूरा करने में विफल रहता है जो स्वतंत्रता के समय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। सबसे अधिक हाशिए पर पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण योजनाओं की आवश्यकता है जो उनका मानवाधिकार है। 1978-79 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित वर्ग का प्रतिशत 51.32 प्रतिशत था जो 1993-94 में घटकर 35.97 प्रतिशत हो गया,हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय गरीबी औसत से ऊपर था। आरक्षण ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को इस मायने में भी मदद की है कि इससे स्नातक,स्नातकोत्तर,तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनका नामांकन बढ़ गया है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति के नामांकन का प्रतिशत 1978-79 में 7.08 प्रतिशत था जो 1995-96 में बढ़कर 13.30 प्रतिशत हो गया। समानता के बिना योग्यता तंत्र निरर्थक है। सबसे पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए।

सराहनीय है एकीकृत पेंशन योजना

डॉ. पीएस वोहरा

इस योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों व उनके परिवारों को प्रत्यक्ष रूप आर्थिक फायदा मिलेगा। ज्ञात रहे कि देश में बीते कई वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के लिए वाजपेयी सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गयी नयी पेंशन स्कीम के प्रति असंतोष व्याप्त था। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान विपक्षी दलों ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को फिर से लागू कर दिया गया। सबसे पहले यह घोषणा राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने की थी। इसका दबाव केंद्र सरकार पर लगातार बना रहा था। पिछले वित्त वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन की नयी योजना बनाने के संबंध में एक कमिटी बनाने की घोषणा की थी। इस कमेटी को अपना एक प्रारूप इस साल लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रस्तुत करना था, जो नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले ही एक नयी और बेहतरीन योजना को मंजूर कर दिया।

इस नयी पेंशन योजना के आने के बाद से एक चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना, जो अंग्रेजों के दौर से शुरू होकर 2004 तक तक लागू रही, की तरफ वापस मुड़ रही है। इस पक्ष पर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ज्ञात रहे कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान पेंशन कोष में कुछ भी अंशदान नहीं देना होता था तथा सेवानिवृत्ति पर पेंशन और मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली पेंशन 100 प्रतिशत सरकारी अंशदान के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। स्वतंत्र भारत में इस योजना को 57 साल तक उपयोग में लाया गया। वर्ष 2004 में इसे समाप्त कर एक ऐसी पेंशन योजना को लागू किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान पेंशन हेतु अपने वेतन का एक हिस्सा नियमित रूप से अंशदान के रूप में देना था। अब 2025 से लागू होने

वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में भी सरकारी कर्मचारियों को 2004 की नयी पेंशन स्कीम की तरह ही अपने वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान पेंशन कोष में जमा करवाना होगा, पर अब इसमें सरकार का अंशदान और बढ़ेगा। यह समझना जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन हेतु अपना अंशदान जमा करवाना होगा, उसमें कोई रियायत नहीं दी गयी है। बीस वर्षों के बाद भारत में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के संबंध में यूपीएस के रूप में एक नयी योजना उपलब्ध हुई है, जो 2004 की नयी पेंशन स्कीम से कई मामलों में बहुत बेहतर है। मसलन, अब सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित रकम की गारंटी पेंशन के रूप में उपलब्ध होने की रहेगी, जो कि एनपीएस में नहीं थी, जबकि कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में दे रहा था।

इस नयी योजना के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि 25 वर्ष तक काम करने के बाद ही अंतिम वर्ष के मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा हर हालत में पेंशन की रकम के रूप में मिलेगा। वहीं अगर सेवा 25 वर्षों से कम की है, तो पेंशन की रकम सेवा के वर्षों के अनुपात में निश्चित होगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि अगर सेवा न्यूनतम 10 वर्षों के लिए की गयी है, तो मासिक पेंशन की रकम 10,000 रुपये निश्चित रहेगी। यह बहुत सराहनीय है। एक अन्य सकारात्मक पक्ष यह भी है कि पेंशनधारी की मृत्यु होने पर मासिक पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी के प्रतिनिधि को प्रति माह मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत महंगाई भत्ते को भी पेंशन की रकम में सम्मिलित किया गया है, जो एनपीएस में नहीं था। हर तीन वर्ष के बाद पेंशन फंड में सरकारी अंशदान की सीमा की बढ़ोतरी के लिए मूल्यांकन किया जायेगा, जो वर्तमान में 18।5 प्रतिशत पर निश्चित किया गया है। कर्मचारी का अंशदान भविष्य में 10 प्रतिशत ही यथावत रहेगा, उसमें इससे अधिक की बढ़ोतरी नहीं होगी।

ऐसे प्रावधानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार की यह पेंशन योजना 2004 की पेंशन योजना का एक बेहतर विकल्प है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2004 की योजना से इस योजना में आने वाले कर्मचारियों को एरियर के रूप में भी भुगतान किया जायेगा, जिसका आर्थिक खर्च करीब 800 करोड़ रुपये का होगा। जहां तक पूर्ववर्ती योजना से एकीकृत पेंशन योजना की तुलना का प्रश्न है, तो यह बताना जरूरी है कि मोदी सरकार ने इस योजना के द्वारा पूरी कोशिश की है कि पुरानी पेंशन योजना के लाभों को वापस कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए। परंतु फिर भी कुछ आयामों पर आज भी पुरानी पेंशन योजना तुलनात्मक रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्यादा सहानुभूति रखती है। एक, उसमें न्यूनतम 20 वर्षों के बाद वेतन के 50 प्रतिशत की रकम का पेंशन के रूप में मिलना निश्चित था, जो अब 25 वर्ष है। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम पुरानी पेंशन योजना की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत से कम रहेगी, जो इस योजना के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस योजना में पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कुछ बेहतर पक्ष भी हैं, जैसे- फैमिली पेंशन के अंतर्गत अब 60 प्रतिशत का हिस्सा दिया जायेगा, जबकि पहले यह 30 प्रतिशत ही था और न्यूनतम पेंशन की सीमा को भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से कर्मचारियों द्वारा इस योजना का स्वागत होगा, पर अधिक उम्मीद होने के कारण कुछ निराशा भी हो सकती है। पेंशन का मुद्दा अभी भी राजनीतिक रहेगा क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को कुछ राज्यों ने पहले से ही लागू किया हुआ है।

अगली संसद में पंजाब से दोनों सदन के सदस्यों का अनुपात घट जाएगा

इकबाल सिंह चन्नी

जैसे -जैसे भारत की लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर लगी 50 साल की रोक खत्म होने वाली है वैसे ही केंद्र और राज्य के राजनीतिक गलियारों में इसके प्रभाव पर बहस शुरू हो गई है क्योंकि इससे यू.पी., बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के सदस्यों की संख्या बढने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटों में इन 4 राज्यों की हिस्सेदारी एक तिहाई से ज्यादा बढ़ जाएगी और केरल और हिमाचल उन राज्यों में से एक होंगे जहां सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी और पंजाब व तमिलनाडु में सीटों में मामूली वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि परिसीमन आयोग को जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ानी है।

जिन राज्यों ने परिवार नियोजन प्रक्रिया को ईमानदारी से लागू किया वहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रही और जिन राज्यों ने इस योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसके चलते परिवार नियोजन योजना को ईमानदारी से लागू करने वाले राज्यों के राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस फॉर्मूले से उन्हें केंद्रीय योजना को ईमानदारी से लागू करने की सजा मिलेगी, जो सही नहीं है। देश में हर 10 साल में जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती थी। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार ने अब तक 4 ऐसे आयोगों की स्थापना की है। पहली बार 1952 में किसी आयोग की स्थापना की गई थी, तब लोकसभा में सीटों की संख्या 494 थी। परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत 1963 में दूसरे परिसीमन आयोग की स्थापना की गई और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 522 कर दी गई। 1972 के परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत 1973 में इस आयोग की स्थापना की गई और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई।

चौथी बार इस आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुलदीप सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 2008 में लागू हुई और उसके बाद से सभी चुनाव इसी रिपोर्ट के आधार पर हो रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट से लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई, लेकिन इस आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन फिर से किया और सामान्य तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में काफी उथल-पुथल हुई क्योंकि इस आयोग की रिपोर्ट एक चुनौती थी इसलिए इस रिपोर्ट को बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से लागू किया गया।

सरकार ने अभी तक जनगणना कराने का निर्णय नहीं लिया है और न ही नए आयोग के गठन को लेकर कोई कार्रवाई शुरू की है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा के नए भवन का निर्माण कराया गया है और इसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटों की व्यवस्था की गई है उससे लगता है कि सरकार समय पर परिसीमन आयोग द्वारा गणना कराकर नए सिरे से सीमांकन करेगी। इस सीमा के बाद, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 846 और राज्यसभा के लिए संख्या 250 से बढ़कर 384 होने की उम्मीद है। राज्यों के हिसाब से देखें तो यू.पी. में 80 से बढ़कर 143, बिहार में 40 से बढ़कर 79, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50 और मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 52 हो जाएंगी। केरल में 20 सीटें, तमिलनाडु में 49 सीटें, पंजाब में 18 सीटें और हिमाचल में 4 सीटें होंगी और इन 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात लोकसभा और राज्यसभा में काफी कम हो जाएगा।

इन 8 राज्यों के अलावा लद्दाख की 1, जम्मू-कश्मीर की 8, चंडीगढ़ की 1, उत्तराखंड की 7, दिल्ली की 12, सिक्किम की 1, असम की 21, अरुणाचल की 2, नागालैंड की 1, मणिपुर की 2, मेघालय की 2 , त्रिपुरा 2, मिजोरम 1, बंगाल 60, झारखंड 24, ओडिशा 28, छत्तीसगढ़ 19, हरियाणा 18, गुजरात 43, महाराष्ट्र 76, कर्नाटक 41, आंध्र और तेलंगाना 54, पुडुचेरी 1, दमन दीव की 2, गोवा की 2, 1 सीट अंडेमान-निकोबार की और लक्षद्वीप की एक सीट परिसीमन के बाद होने की संभावना है।

विपक्षी दलों के कई नेता कई बार जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध कर चुके हैं। केरल, पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों से संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या का अनुपात बहुत कम हो जाएगा। जनसंख्या आधारित परिसीमन का दक्षिणी राज्यों ने कड़ा विरोध किया है, यहां तक कि तमिलनाडु विधानसभा ने भी परिसीमन के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पंजाब के राजनीतिक नेता इस मुद्दे पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा शुरू नहीं की है और न ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे में संपर्क किया है। परिसीमन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की सफाई देते हुए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन के मुद्दे पर उत्तर-दक्षिण राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठेंगे और विचार करेंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे को सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। इस वजह से यह डर बना हुआ है।

राजनीतिक परिवारों की महिलाएं और राजनीति

कल्याणी शंकर

कुछ नेता चुनावों के दौरान उभरते हैं, जैसे कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव। ऐसी ही एक शख्सियत हैं 59 वर्षीय सुनीता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। वे अपने जेल में बंद पति और पार्टी के बीच अहम कड़ी बन गई हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी वे पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगी या नहीं, यह अभी तय नहीं हो पाया है। राजनीतिक परिवारों की महिलाएं अक्सर अपने रिश्तेदारों की जगह राजनीति में उतरती हैं। इसका एक सफल उदाहरण सोनिया गांधी हैं। एक और उल्लेखनीय मामला राबड़ी देवी का है। उन्होंने 2000 से 2005 तक बिहार का नेतृत्व किया, जब उनके पति को कथित तौर पर घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। सुनीता के पास अनुभव और ठोस पेशेवर पृष्ठभूमि है। आयकर विभाग में उनका 22 साल का कार्यकाल, जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) में आयकर आयुक्त के रूप में समाप्त हुआ, उनकी योग्यता को दर्शाता है। दरअसल, सुनीता ने अपने पति की राजनीतिक यात्रा को कम प्रोफाइल के साथ आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ने खुद को एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर पेश किया और लोकसभा चुनावों के दौरान सुनीता के साथ प्रचार किया। खासकर केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में सुनीता की बढ़ती भागीदारी उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। केजरीवाल के इस्तीफा देने पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी संभावित भूमिका के बारे में अटकलें 'आप' की राजनीति में एक नया नजरिया ला सकती हैं। दूसरी बात, सुनीता का नेतृत्व इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी संकट से जूझ रही है। कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। केंद्र ने उन्हें लंबे समय तक मौका दिया है और संवैधानिक विफलता के आधार पर उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में विधानसभा चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं, जिससे आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया का सुझाव है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में सुनीता की भूमिका खत्म हो जाएगी। 'आप' के संस्थापक और सदस्य सिसोदिया केजरीवाल के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 'आप' सांसद संजय सिंह का दावा है कि केजरीवाल के संदेशवाहक के रूप में सुनीता की भूमिका बढ़ रही है। फिर भी, केजरीवाल का कहना है कि सुनीता की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। हालांकि सुनीता को कामचलाऊ विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव के कारण उन्हें किनारे करना चुनौतीपूर्ण है। अगर केजरीवाल को जमानत भी मिल जाती है, तो यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी में सुनीता की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। चौथा, पार्टी को आगामी हरियाणा और दिल्ली चुनावों के मद्देनजर नैतिक बढ़ावे की जरूरत है; 'आप' को एक विश्वसनीय नेता और कुछ नैतिक बढ़ावे की जरूरत है। सुनीता इस कमी को पूरा करती हैं। पांचवां, 'आप' के सदस्यों ने फिलहाल सुनीता को ही कड़ी के रूप में स्वीकार कर लिया है। पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल होने के बावजूद सुनीता 'आप' में कोई आधिकारिक पद नहीं रखती हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार किया है और अभी हरियाणा में प्रचार शुरू किया है। उनका बचाव यह था कि कुछ राजनीतिक ताकतें उनके पति को बदनाम करने में शामिल थीं। विपक्षी गठबंधन ने सुनीता की बढ़ती भागीदारी और स्वीकार्यता को स्वीकार किया है। हाल ही में रामलीला मैदान में एक रैली में उन्हें सोनिया गांधी के साथ एक प्रमुख स्थान पर बैठाया गया था। सुनीता ने पिछले सप्ताह आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अभियान की शुरूआत करते हुए 'केजरीवाल की गारंटी' (मुफ्त) लॉन्च की। इन गारंटियों में मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, हर महिला को 1,000 रुपए मासिक सहायता और युवाओं के लिए रोजगार शामिल हैं। सुनीता के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। केजरीवाल की राजनीतिक सफलता के बावजूद, उन्हें राजनीति में अनुभव नहीं है और वे आप की सदस्य भी नहीं बनी हैं। उनके नेतृत्व के गुणों को अभी भी स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या वह कठोर निर्णय ले पाएंगी और पार्टी को एकजुट रख पाएंगी, यह अभी भी तय किया जा रहा है। फिलहाल उनका सीमित उद्देश्य पार्टी को एकजुट रखना है। ऐसी अनिश्चित स्थिति में उन्हें सीमित तरीके से काम करना होगा।

कृष्ण पूर्णतया निर्विकारी हैं। तभी तो उनके अंगों के साथ भी लोग 'कमल' शब्द जोड़ते हैं, जैसे- कमलनयन, कमलमुख, करकमल आदि। उनका स्वरूप चैतन्य है। कृष्ण ने तो द्रोपदी का चीर बढ़ाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का दिन बड़ा ही पवित्र है। जैनियों के भावी तीर्थंकर और वैदिक परंपरा के नारायण श्रीकृष्ण के अवतरण का दिन है।

सोलह कलाओं के अवतार हैं

श्रीकृष्ण

भगवान श्रीकृष्ण को सोलह कलाओं का अवतार माना जाता है। सच में कृष्ण ने समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान बढ़ाया, जो जिस भाव से सहायता की कामना लेकर कृष्ण के पास आया, उन्होंने उसी रूप में उसकी इच्छा पूरी की। अपने कार्यों से उन्होंने लोगों का इतना विश्वास जीत लिया कि आज भी लोग उन्हें 'भगवान श्रीकृष्ण' के रूप में ही मानते और पूजते हैं।

कृष्ण पूर्णतया निर्विकारी हैं। तभी तो उनके अंगों के साथ भी लोग 'कमल' शब्द जोड़ते हैं, जैसे- कमलनयन, कमलमुख, करकमल आदि। उनका स्वरूप चैतन्य है। कृष्ण ने तो द्रोपदी का चीर बढ़ाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का दिन बड़ा ही पवित्र है। जैनियों के भावी तीर्थंकर और वैदिक परंपरा के नारायण श्रीकृष्ण के अवतरण का दिन है। कृष्ण ने सारी दुनिया को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। उन्होंने प्राणीमात्र को यह संदेश दिया कि केवल कर्म करना आदमी का अधिकार है। फल की इच्छा रखना उसका अधिकार नहीं। इंसान सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करता है। श्रीकृष्ण का जीवन भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उनके जीवन को हम तीन भागों में विभक्त करें तो वे जेल में पैदा हुए, महल में जिए और जंगल से विदा हुए। जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में जीना और मरना अपराध हुआ करता है। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। भगवान श्रीकृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान महावीर आदि महापुरुषों ने हमें जीवन जीने की सीख दी है। राम, कृष्ण एवं महावीर का जीवन अलग-अलग मर्यादाओं और संदेशों पर आधारित है। राम ने जीवन भर मर्यादाएं नहीं तोड़ीं, वे देव बनकर जिए। श्रीकृष्ण वाकपुटता में जीवन जीते रहे। मर्यादाओं से नीरस हुए जीवन को कृष्ण ने रस और आनंद से भर दिया, लेकिन महावीर ने परम विश्राम और समाधि का सूत्र दिया। उन्होंने मौन साधना सिखाई। मित्रता सीखनी हो तो कृष्ण से सीखो वे सबको अपने समान चाहते थे। उनकी दृष्टि में अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं था। अतः हमें भी कृष्ण की इसी सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

व्रत-पूजन कैसे करें

उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें।

उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं।

तत्पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें।

इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें

ममखिलपापप्रशमनपूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहं करिष्ये॥

अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकीजी के लिए सूतिकागृह नियत करें।

तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

मूर्ति में बालक श्रीकृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मीजी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हो।

इसके बाद विधि-विधान से पूजन करें

पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम क्रमशः निर्दिष्ट करना चाहिए।

फिर इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें-

प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः।
वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः।
सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं में गृहाणेमं नमोऽस्तुते।

अंत में प्रसाद वितरण कर भजन-कीर्तन करते हुए रतजगा करें।

श्रीकृष्ण बना रहे

मालामाल

जन्माष्टमी पर इन्हीं पोशाकों को धारण कर ठाकुरजी अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देकर निहाल करेंगे। ब्रज के लाला के जन्मोत्सव की तैयारियां हिंदू ही नहीं, यहां का मुस्लिम समाज भी कर रहा है। ठाकुरजी को पहनाई जाने वाली पोशाकें और मुकुट शृंगार को तैयार करने में मुस्लिम समाज के कारीगर दिन रात एक करने लगे हैं।

भगवान श्रीकृष्ण दीन दयाल कहलाते हैं। जो भी इनकी शरण में आ जाता है, उसे धनवान बना देते हैं। श्रीकृष्ण की कृपा से हिंदू हमेशा से धनवान होते रहे हैं, लेकिन श्रीकृष्ण की लीलास्थली में मुसलमान भी श्रीकृष्ण की कृपा से निहाल हो रहे हैं और श्रीकृष्ण उन्हें मालामाल बना रहे हैं।

ऐसे कृपा बरस रही है कृष्ण की

वृंदावन के मुसलमानों को श्रीकृष्ण इसलिए मालामाल बन रहे हैं कि यहां के मुसलमान हिंदुओं की आस्था के केंद्र ठाकुर जी के लिए पूरी निष्ठा के साथ एक से बढ़कर एक शानदार पोशाकें, मुकुट शृंगार तैयार कर रहे हैं।

जन्माष्टमी पर इन्हीं पोशाकों को धारण कर ठाकुरजी अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देकर निहाल करेंगे। ब्रज के लाला के जन्मोत्सव की तैयारियां हिंदू ही नहीं, यहां का मुस्लिम समाज भी कर रहा है। ठाकुरजी को पहनाई जाने वाली पोशाकें और मुकुट शृंगार को तैयार करने में मुस्लिम समाज के कारीगर दिन रात एक करने लगे हैं। कई परिवार वर्षों से ठाकुरजी की पोशाक और मुकुट शृंगार को मूर्त रूप प्रदान करते आए हैं। यह हमारी जीविका का साधन भी है। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों का पालन ठाकुरजी की पोशाक और शृंगार के निर्माण से चल रहा है।

विदेशों में भी इनके कपड़े पहनते हैं श्रीकृष्ण

वृंदावन के मुस्लिम समाज द्वारा बनाई गई पोशाक गुजरात के अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम के राधा-कृष्ण के श्री विग्रह और दिल्ली एवं पंजाबी बाग के इस्कान मंदिर के श्री विग्रह धारण करेंगे। वृंदावन में बनाई जाने वाली पोशाकों की मांग इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया के भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी भी अधिक पसंद करते हैं। वे वृंदावन से खरीदकर अपने अपने देश ले जाते हैं।

राधा और कृष्ण का आपस में

कैसा नाता

भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के बारे में यह माना जाता है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था, जबकि असलियत यह है कि कृष्ण और राधा के बीच प्रेम से बढ़कर भी एक नाता था। यह नाता है पति-पत्नी का, लेकिन इस रिश्ते के बारे में सिर्फ तीन लोगों को पता था- एक तो कृष्ण, दूसरी राधा रानी और तीसरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था, लेकिन इन तीनों में आपके कोई भी इस बात की गवाही देने नहीं आएगा, लेकिन जिस स्थान पर इन दोनों का विवाह हुआ था, वहां के वृक्ष आज भी राधा-कृष्ण के प्रेम और मिलन की गवाही देते हैं।

तब राधा-कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ

गर्ग संहिता के अनुसार, मथुरा के पास स्थित भांडीर वन में भगवान श्रीकृष्ण और देवी राधा का विवाह हुआ था। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार नंदराय जी बालक श्रीकृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक देवी राधा प्रकट हुई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी ने श्रीकृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्रीकृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया।

राधा जी की मांग में सिंदूर

भांडीर वन में राधाजी और भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है, जिसमें श्रीकृष्ण भगवान राधाजी की मांग में सिंदूर भरते हुए दृश्य हैं।

भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश

गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त कर्म यानी 'फल की इच्छा किए बिना कर्म' करने की प्रेरणा दी। इसका प्रमाण उन्होंने अपने निजी जीवन में भी प्रस्तुत किया। मथुरा विजय के बाद भी उन्होंने वहां शासन नहीं किया।

कला से प्रेम करो : संगीत और कलाओं का हमारे जीवन में विशिष्ट स्थान है। भगवान ने मोरपंख और बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति एवं पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया। इनके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि जीवन को सुंदर बनाने में संगीत और कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

निर्बल का साथ दो : कमजोर एवं निर्बल का सहारा बनो। निर्धन बाल सखा सुदामा हो या षड्यंत्र का शिकार पांडव, श्रीकृष्ण ने सदा निर्बलों का साथ दिया और उन्हें मुसीबत से उबारा।

अन्याय का प्रतिकार करो : अन्याय का सदा विरोध होना चाहिए। श्रीकृष्ण की शांतिप्रियता कायर की नहीं, बल्कि एक वीर की थी। उन्होंने अन्याय कभी स्वीकार नहीं किया। शांतिप्रिय होने के बावजूद शत्रु अगर गलत है तो उसके शमन में पीछे नहीं हटें।

मातृशक्ति के प्रति आदर भाव रखें : महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें साथ लेकर चलने का भाव हो। भगवान कृष्ण की रासलीला दरअसल मातृशक्ति को अन्याय के प्रति जागृत करने का प्रयास था और इसमें राधा उनकी संदेशवाहक बनीं।

अपने अहंकार को छोड़ो : व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सहज एवं सरल बने रहो। जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर भी श्रीकृष्ण को न तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और न ही अर्जुन का सारथी बनने में। एक बार तो दुर्योधन के छप्पन व्यंजन को छोड़कर विदुरानी (विदुर की पत्नी) के घर उन्होंने सादा भोजन करना पसंद किया।

जीवन में उदारता रखें : उदारता व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। श्रीकृष्ण ने जहां तक हो सका मित्रता, सहयोग सामंजस्य आदि के बल पर ही परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जहां जरूरत पड़ी, वहां सुदर्शन चक्र उठाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। वहीं अपने निर्धन सखा सुदामा का अंत तक साथ निभाया और उनके चरण तक पखारें।

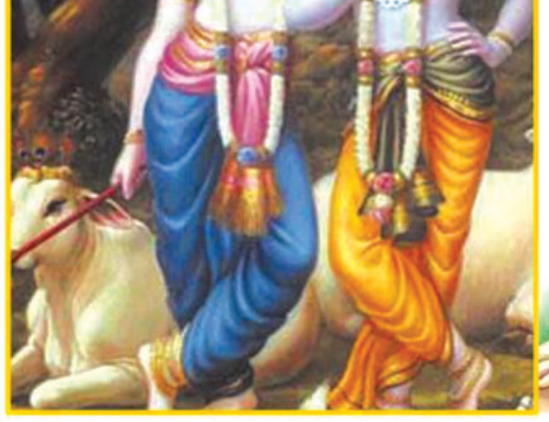

कविताएं

चन्दन की खुशबू, फूलों का हार

चन्दन की खुशबू, फूलों का हार,
दही की हांडी, बारीश की फुहार,
माखन चुराने आया नंदलाल,
यशोमती मैया का नंदगोपाल !

राधा की भक्ति, मुरली की मिठास,
माखन का स्वाद और गोपियों का रास,
इन्ही सबसे मिलकर बनता है,
जन्माष्टमी का ये दिन ख़ास !

मुरली मनोहर, ब्रिज के धरोहर,
मुरली की मधुर आवाज़, झूम उठे ये बहार,
कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम,
श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम !

कान्हा

द्वापर में भादों के महीने में
काली अंधेरी रात में
जन्म लिया कान्हा ने
मथुरा में कारागार के कक्ष में।
था दिवस चमत्कारी
सारे बंधन टूट गए
द्वार के ताले स्वत : खुले
जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
बेटे को बचाने के लिए
गोकुल जाने के लिए
वासुदेव ने जैसे ही
जल में पैर धरा
जमुना की श्रद्धा ऐसी जागी
बाढ़ आ गई नदिया में।
बाहर पैर आते ही
कान्हा के पैरों को पखारा
जैसें ही छू पाया उन्हें
अद्भुत शांति छाई जल में।
सारा गोकुल धन्य हो गया
कान्हा को पा बाहों में
गोपिया खो गई
मुरली की मधुर धुन में।
बंधीं प्रेम पाश में उसके
रम कर रह गईं उसी में
ज्ञान उद्धव का धरा रह गया
उनको समझाने में।
वे नहीं जानती थीं उद्देश्य
कृष्ण के जाने का
कंस के अत्याचारों से
सब को बचाने का।
अंत कंस का हुआ
सुखी समृद्ध राज्य हुआ
कौरव पांडव विवाद में
मध्यस्थ बने सहायता की।
सच्चाई का साथ दिया
युद्ध से विचलित अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया
आज भी है महत्व जिसका।
जन्म दिन कान्हा का
हर साल मनाते हैं
श्रद्धा से भर उठाते हैं
जन्माष्टमी मनाते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केंद्र सरकार बनाएगी लद्दाख में 5 नए जिले : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाने की तैयारी है। यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार, नए जिले ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, और नए जिले सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले, अर्थात् ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बात की। दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग का जायजा लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बता दें कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने यूरोपिय देश पोलैंड और यूक्रेन का दौरा कर भारत लौटे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अपने दोस्त एंथनी अल्बनीज से बात करके खुशी मिली। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग का जायजा लिया। बता दें कि क्वाड चार देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सुरक्षा समूह का संवाद है। साल 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इसका विचार दिया था और साल 2017 में क्वाड गठन किया गया।

मायावती ने की भाजपा की तारीफ, कांग्रेस पर उठाए सवाल

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर एससी-एसटी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र में सरकार होते हुए भी कांग्रेस ने अपना दायित्व नहीं निभाया था। इस दौरान मायवती ने भाजपा की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें बचाया था। मायावती ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की। इसमें लिखा सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापिसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है? जबकि उस दौरान केन्द्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था।

भाजपा ने जारी की पहली सूची 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया। सूची के मुताबिक, पाम्पोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपोरा से अर्शीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, इंदरबल से तारिक कीन, डोडा से गजय सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर-नागसेनी से सुनील शर्मा, भदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार, रामबाण से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट को उम्मीदवार है। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए भाजपा ने 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।

रजनीकांत के बयान पर तमिलनाडु में सियासी भूचाल

चेन्नई। फिल्म अभिनेता रजनीकांत के बयान को लेकर तमिलनाडु में सियासी भूचाल आ गया है। ष्ठरूच नेताओं ने रजनीकांत को घेरना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता दुरई मुरुगन ने रविवार को पुराने छात्र वाले बयान पर अभिनेता रजनीकांत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिल्मों में भी कुछ पुराने अभिनेता ऐसे हैं जो युवा कलाकारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। दरअसल शनिवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि पर एक पुस्तक विमोचन समारोह में अभिनेता रजनीकांत ने कहा था कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि एक स्कूल में शिक्षक (एमके स्टालिन) को नए छात्रों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी समस्या पुराने छात्रों को संभालने में होती है। क्योंकि पुराने छात्र सामान्य नहीं हैं। वे तो रैंक धारक छात्र हैं और कक्षा (डीएमके) को नहीं छोड़ेंगे। खासकर तब जब पार्टी में दुरई मुरुगन जैसे नेता हों।

पंजाब-कश्मीर से लेकर अरुणाचल-सिक्किम-मिजोरम तक में बदलीं चुनाव तारीखें

नईदिल्ली। हरियाणा में 1 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तय है। हालांकि, भाजपा समेत कुछ दलों ने चुनाव कार्यक्रम में बदलाव की मांग की है। इसको लेकर भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। पार्टी ने छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीख बदलने की बात कही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आयोग चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है।

हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में चुनाव की तारीखों में परिवर्तन की मांग उठी हो। हाल में लोकसभा के साथ हुए दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली थीं।

चुनाव कार्यक्रम में अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख तक की सभी तारीखें शामिल होती हैं। इसमें मतदाताओं के लिए, कार्यक्रम में दो सबसे अहम तिथियां मतदान और मतगणना की तारीखें होती हैं।

निर्वाचन आयोग, लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने के छह महीने के भीतर किसी भी समय चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 में किया गया है। चुनाव प्रक्रिया, लोकसभा या राज्य विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरी होनी चाहिए। चुनाव कार्यक्रम तय करते समय, आयोग सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए उपलब्धता और आवश्यकताओं, ईवीएम और चुनाव अधिकारियों की व्यवस्था के साथ-साथ प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों और मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी देखता है।

यदि कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लगभग एक ही समय पर खत्म हो रहा है, तो चुनाव आयोग चुनाव एक साथ कराने का प्रयास करता है। मतदान भले ही अलग-अलग दिनों में हो, लेकिन मतगणना आमतौर पर एक ही दिन होती है।

पहले किन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम बदला

जम्मू कश्मीर- निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च, 2024 को लोकसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके, तीसरे चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल, 2024 को जारी की गई थी और मतदान का दिन 7 मई 2024 को निर्धारित किया गया था। विभिन्न लॉजिस्टिक, संचार और मौसम संबंधी दिक्कतों के चलते राजनीतिक दलों ने जम्मू- कश्मीर की 3-अनंतनाग-राजौरी संसदीय सीट पर चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। इसके बाद मतदान की तिथि 7 मई, 2024 (चरण-3) को बदलकर 25 मई, 2024 (चरण-6) कर दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम- लोकसभा चुनाव के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। चुनाव आयोग ने 16 मार्च, 2024 को आम चुनाव के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं और लोकसभा के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। आयोग ने पहले अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान की तारीख 19 अप्रैल, 2024 और मतगणना की तारीख 4 जून, 2024 तय की थी। जबकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून, 2024 को समाप्त होने वाला था। नियमों के अनुसार, निर्वाचन आयोग को विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कराने होते हैं। इसे देखते हुए, आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए आम चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया था।

मतगणना की तिथि 4 जून, 2024 थी जिसे बदलकर 2 जून, 2024 कर दिया गया। 6 जून, 2024 के पहले चुनाव प्रक्रिया पूरा होनी थी जिसे बदलकर 2 जून, 2024 कर दिया गया था।

मिजोरम- 3 दिसंबर 2023 को मिजोरम समेत पांच राज्यों में विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती होनी थी। मतगणना शुरू होने में लगभग 36 घंटे पहले चुनावा आयोग ने तारीख में बदलाव की घोषणा की। मिजोरम विधानसभा के लिए मतों की गिनती एक दिन की देरी करते हुए इसे 4 दिसंबर, 2023 कर दिया गया था। उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि ईसाई बहुल राज्य में अधिकांश लोग रविवार की सुबह चर्च जाते हैं। रविवार का दिन मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसलिए मतगणना के लिए उपयुक्त नहीं है।

पंजाब- 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख 14 फरवरी तय की गई थी। इसके दो दिन बाद रविदास जयंती थी। पंजाब के काफी लोग रविदास जयंती मनाने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते हैं। राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी गई थी।

महाराष्ट्र में उद्धव और एकनाथ के बीच जारी है प्रतिद्वंद्विता

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सबसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दोनों राजनेता एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं और जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वे एक-दूसरे को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल, दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक ही है- एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना।

ठाकरे और शिंदे दोनों की महत्वाकांक्षा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) ने विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है, ठाकरे के करीबी सहयोगी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें एमवीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। ठाकरे ने इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली का दौरा किया था, तब भी उन्होंने इस बात की संभावना जताई थी।

राजनीतिक विभाजन के दूसरी तरफ, शिंदे की शिवसेना उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने के लिए उत्सुक है। कहा जाता है कि शिंदे ने भी अपने दिल्ली दौरों के दौरान इस संभावना का लाभ उठाया है। हालांकि, दोनों ही एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं- उनके सहयोगी उनसे सहमत नहीं हैं। ठाकरे के मामले में, कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि शीर्ष पद अधिकतम सीटों वाली पार्टी को मिलना चाहिए। एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार, जिन्होंने 2019 में एमवीए सरकार के गठन के समय शीर्ष पद के लिए ठाकरे का नाम सुझाया था, ने अब तक शिवसेना (यूबीटी) की मांग का समर्थन नहीं किया है।

सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा ने शिंदे को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी है। जहां तक ??तीसरे साथी एनसीपी का सवाल है, तो पार्टी अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित करने में व्यस्त है। इस बीच, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने राजनीतिक हलकों में एक चुटकुला साझा किया। 2019 में शिवसेना को मुख्यमंत्री न दिए जाने के मुद्दे पर भगवा गठबंधन टूट गया था। इसके बाद, महाराष्ट्र में पिछले पांच सालों में कई बड़े राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिले, लेकिन विडंबना यह है कि इस दौरान मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास ही रहा- पहले ढाई साल ठाकरे और बाकी आधे साल शिंदे!

पिछले हफ्ते वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आई एस चहल को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) नियुक्त किए जाने के बाद, अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक राज्य चुनाव आयुक्त का पद चुनेंगी जो अगले महीने खाली हो रहा है। अगर ऐसा होता है, तो चहल मुख्य सचिव पद के लिए शीर्ष दावेदार होंगी। गृह सचिव का पद वैसे भी राज्य प्रशासन में शीर्ष पद से बस एक कदम दूर माना जाता है। सौनिक ने अभी तक एसईसी पद के लिए आवेदन नहीं किया है। अगर वह इसे चुनती हैं तो उन्हें वहां लंबा कार्यकाल मिलेगा।

जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चहल को अगला मुख्य सचिव देखना चाहते हैं, वहीं भाजपा और एनसीपी के उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी सोच रहे हैं कि क्या सौनिक के कार्यकाल का एक साल पूरा होने से पहले ही उनकी जगह किसी पुरुष अधिकारी को नियुक्त करना गठबंधन सरकार की महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के विपरीत होगा, खासकर तब जब गठबंधन सरकार ने उन्हें राज्य का पहला मुख्य सचिव नियुक्त करने का श्रेय लिया था। अगर सौनिक एसईसी पद नहीं चुनती हैं तो वह 2025 के मध्य तक मुख्य सचिव के पद पर बनी रह सकती हैं।

पवार परिवार के दो युवा सदस्य प्रतिद्वंद्वी खेमे से बारामती क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जल्द ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय और उनके भतीजे युगेंद्र विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और ग्रामीणों से मिल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में अजीत पवार ने कहा था कि वे बारामती से चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि जय उस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से 1991 से उनके पिता चुनाव जीतते आ रहे हैं। दूसरी ओर, युगेंद्र जिन्होंने परिवार में फूट के बाद शरद पवार का साथ दिया और लोकसभा चुनाव में अपनी बुआ सुप्रिया सुले के लिए प्रचार किया, वे लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के हर गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्हें बारामती विधानसभा क्षेत्र में अजीत या जय के खिलाफ एनसीपी (सपा) के संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। बारामती में पारिवारिक ड्रामा अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है।

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा बुलाए गए बंद से पहले तीनों पार्टियों के बीच एकमतता नहीं दिखी। गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर बंद की घोषणा करने के बजाय शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने अलग-अलग घोषणाएं कीं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि बंद दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। जब हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक करार दिया, तो शरद पवार ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने गठबंधन सहयोगियों से बंद वापस लेने की अपील की, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उनसे बात की और अपने विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की।

खेल
प्रमुख समाचार

सूर्यकुमार यादव, श्रेयस और सरफराज पर रहेगी निगाहें

नईदिल्ली। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अपना टेस्ट करियर पटरी पर लाने के लिए बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जिसमें उनकी टीम मुंबई मंगलवार से यहां शुरू होने वाले मैच में टीएनसीए एकादश का सामना करेगी। श्रेयस अय्यर भी मुंबई की टीम का हिस्सा हैं और वह भी सत्र की शुरुआत में होने वाले इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे।

अय्यर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी में खेला था। कई स्टार खिलाड़ियों से सजी मुंबई की टीम का नेतृत्व सरफराज खान करेंगे जिनके लिए सभी शीर्ष खिलाड़ियों की वापसी के बाद टेस्ट टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। सरफराज ने इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करके अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था।

विराट कोहली, केएल राहुल और ऋषभ पंत अलग-अलग कारण से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे लेकिन उनके बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है। बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दौर के मैच में सभी का ध्यान निश्चित तौर पर सूर्यकुमार पर रहेगा जिन्होंने अपना एकमात्र टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी 2023 में खेला था। सूर्यकुमार ने इसके बाद सीमित ओवरों की क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। बुची बाबू टूर्नामेंट सूर्यकुमार और अन्य स्टार खिलाड़ियों के लिए दलीप ट्रॉफी के लिए अभ्यास का काम करेगा। दलीप ट्राफी पांच सितंबर से शुरू होगीं। सूर्यकुमार ने अपना अंतिम प्रथम श्रेणी मैच पिछले साल दलीप ट्राफी में ही खोला था। तब वह चार पारियों में केवल 71 रन बना पाए थे। सरफराज ने इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 612 अंक चढ़ा निफ्टी 25,000 के पार

नईदिल्ली। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को लगभग 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। विदेशी फंड फ्लो और प्रमुख शेयरों एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी से भी बाजार में तेजी आई। इसके अलावा, पॉजिटिव ग्लोबल रुझानों से भी बाजार को मजबूती मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 611.90 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त लेकर 81,698.11 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 81,278.44 और 81,824.27 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 187.45 अंक या 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,010.60 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,874.70 और 25,043.80 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

आरबीआई नीतियां बनाने पर लगातार काम कर रहा : दास

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक लगातार ऐसी नीतियां, प्रणालियां और मंच तैयार करने पर काम कर रहा है जो वित्तीय क्षेत्र को मजबूत, जुझारू और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे। आरबीआई@90 पहल के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में दास ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकियां दुनिया में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की भविष्य की यात्रा को आकार देंगी। डीपीआई व्यापक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित बुनियादी प्रौद्योगिकी प्रणालियों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं तथा अन्य डेवलपर के लिए खुले तौर पर उपलब्ध हैं। दास ने कहा कि पिछले दशक में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व प्रौद्योगिक बदलाव हुआ है।

भारत में कारोबार बढ़ाने को उत्सुक है कैथे कार्गो

नईदिल्ली। हांगकांग स्थित कैथे कार्गो के निदेशक टॉम ओवेन ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में विस्तार करने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं उनके मालवाहक विमानों को देश के भीतर 'ओपन स्काई पॉलिसी' के तहत कई गंतव्यों के बीच उड़ान भरते समय सफर एक साथ पूरा करने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार 'ओपन स्काई पॉलिसी' के तहत कई विदेशी मालवाहकों को सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से परिचालन की अनुमति देती है, ताकि वस्तुओं की आवाजाही में तेजी लाई जा सके और खासकर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ओवेन ने एक साक्षात्कार में कहा, भारत के लिए 'ओपन स्काई पॉलिसी' एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा, इसके अलावा हम यह भी चाहेंगे कि हमारी उड़ानें एक साथ सफर पूरा करें। हम दिल्ली से उड़ान भरने के बाद कोलकाता और फिर हांगकांग वापस जाना पसंद करेंगे, ताकि हम दो स्थानों पर उड़ान भर पाएं।

भेल को अदाणी पावर से मिला 11 हजार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को तीन ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का ठेका मिला है। इस राशि में जीएसटी शामिल नहीं है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बीएसई को दी सूचना में बताया, बीएचईएल ने रविवार (25 अगस्त) को तीन बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों (बॉयलर, टरबाइन, जेनरेटर) की आपूर्ति और स्थापना व उसे चालू कराने की प्रक्रियाओं के लिए अदाणी पावर और उसकी अनुषंगी कंपनी (महान एनर्जीन लिमिटेड) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी सूचना के अनुसार, इन तीन ठेकों का मूल्य 11,000 करोड़ से अधिक है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।

घर और बाहर, दोनों से निवेश आना चाहिए, तभी आएगी स्थिरता

अजय बग्गा

हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में शेयरों के स्वामित्व में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। शेयरों के स्वामित्व के मामले में घरेलू निवेशक विदेशी निवेशकों से आगे निकल रहे हैं। ऐसे में इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले कारकों, भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए इसके निहितार्थ और भारत में घरेलू और विदेशी निवेश के भावी दृष्टिकोण को समझना दिलचस्प है। पारंपरिक रूप से, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), जिन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भी कहा जाता है, भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख भूमिका निभाते थे। उनकी भागीदारी से पर्याप्त पूंजी प्रवाह हुआ, जिससे बाजार में तरलता और समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिला। हालांकि, 2010 के दशक के अंत और 2020 के दशक की शुरुआत में परिदृश्य बदलना शुरू हो गया, क्योंकि खुदरा और संस्थागत निवेशकों सहित घरेलू निवेशकों ने बाजार में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया।

वित्त वर्ष 2014 से, जब एफआईआई स्वामित्व 22 फीसदी था और घरेलू खुदरा और घरेलू संस्थागत स्वामित्व 18 फीसदी था, संरचना उलटने लगी। वित्त वर्ष 2024 में एफआईआई स्वामित्व 18 फीसदी तक कम हो गया है, जबकि घरेलू स्वामित्व 24 फीसदी तक बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय परिवारों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा बैंक जमा, सोना और रियल एस्टेट जैसे पारंपरिक साधनों में लगाया है। लेकिन हाल के वर्षों में शेयर बाजारों में उनकी रुचि बढ़ती देखी गई है। अनुमान है कि 2024 तक भारत में कुल घरेलू बचत का लगभग 8-10 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाएगा। यह भारतीय

परिवारों में शेयर बाजार निवेश की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

खुदरा निवेश में यह वृद्धि कई कारणों से हुई है, जिसमें बढ़ी हुई वित्तीय साक्षरता, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रसार और शेयर बाजार तक आसान पहुंच भी शामिल है। कोविड-19 महामारी ने इसे और तेज कर दिया, जिससे नए डीमैट खातों और बाजारों में नए निवेशकों के प्रवेश में उछाल आया। पिछले एक दशक में भारतीय शेयर बाजारों के शानदार प्रदर्शन ने खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया। पारंपरिक बचत साधनों की तुलना में उच्चतर रिटर्न की संभावना ने परिवारों को अपनी बचत का अधिकाधिक हिस्सा शेयर में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ईएलएसएस) जैसी कर-बचत योजनाओं ने शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित किया है, जिससे यह अधिक आकर्षक बन गया है। युवा आबादी वित्तीय बाजारों में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न सरकारी पहलों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फंड का एक हिस्सा शेयर बाजारों में निवेश करने के सरकारी आदेश से भी घरेलू निवेशक श्रेणी में पर्याप्त प्रवाह हुआ है। भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ने विदेशी निवेशकों को सतर्क बना दिया है। इसके विपरीत, घरेलू निवेशक, जो अक्सर वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक लचीले होते हैं, ने निवेश करना जारी रखा है। भारतीय विनियामक ढांचा घरेलू निवेशकों को सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई पहलों ने स्थानीय निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने और सकारात्मक विकास संभावनाओं ने घरेलू निवेशकों को बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और विनिर्माण पर सरकार के जोर देने से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

8 माह में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर : बीजापुर में 25 खूंखार माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर. राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और बीजापुर पुलिस के 'नियद नेल्ला नार' योजना से प्रभावित होकर 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इसमें 8-8 लाख के ईनामी कंपनी नंबर 02 के 03 PLGA/पार्टी सदस्य, 03 लाख का ईनामी प्लाटून नम्बर 16 सेक्शन डिप्टी कमाण्डर, 01-01 लाख के ईनामी 02 माओवादी एलओएस सदस्य-सीएनएम अध्यक्ष सहित भैरमगढ़ एरिया कमेटी एवं गंगालूर एरिया कमेटी के माओवादी शामिल हैं. बता दें कि 2024 में अब तक 170 माओवादियों ने सरेंडर किया है.

बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से अपना रास्ता बदलने की बात कही थी नहीं तो अंतिम प्रहार की चेतावनी दी थी. जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करने की बात भी कही थी. इसका असर बस्तर में दिखने मिला है. माओवादियों की भेदभाव पूर्ण नीति, माओवादियों के जीवन शैली व विचारधारा से क्षुब्ध होकर एवं छग शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति एवं बीजापुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

सरेंडर किए माओवादियों को दिए गए 25-25 हजार रुपए-बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया, वर्ष 2024 में अब तक 170 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 346 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत् 25000-25000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि दी गई.

पीयूसीएल ने बस्तर की तुलना गाजा से की, फर्जी मुठभेड़ में बेकसूर आदिवासियों को मारने का लगाया आरोप

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने जगदलपुर में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. दो दिनों के दौरान 70 लोगों का वीडियो बयान लेकर पिछले 8 से 10 महीनों में बस्तर के अलग स्थानों में फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया.

पीयूसीएल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील कोलिन गोंसाल्वेस ने सेमिनार के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षाबलों की गोलियों से बेकसूर आदिवासियों के मारे जाने की बात कही. इसके साथ ही विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने बस्तर की तुलना गाजा से की. इस दौरान मूलवासी बचाओ मंच से जुड़ी सोनी सोढ़ी ने भी बस्तर में फर्जी मुठभेड़ किए जाने का आरोप लगाया. वहीं नक्सलियों के साथ सरकार की शांति वार्ता को लेकर सोनी सोढ़ी ने कहा कि अगर सरकार शांति वार्ता करना चाहती है, तो मानवता के नाते सरकार और नक्सलियों के बीच मेडियेटर बनने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि हम सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं. पीयूसीएल के फर्जी मुठभेड़ के आरोप को साय सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने झूठा करार देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हमारा पूछा छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा.

केदार कश्यप ने झूठा करार दिया

नवा रायपुर में चौक-चौराहों के नामकरण पर बोले उपमुख्यमंत्री शर्मा

'पिछली सरकार में जो नाम किए सो किए, अब आगे काम हमारा है'

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नामकरण की राजनीति नई नहीं बहुत पुरानी है. सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं से लेकर चौक-चौराहों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के नामकरण को लेकर सियासत होती रही है. सरकारें किसी की भी रही हो नामकरण को लेकर सियासी बवाल मचते रहा है. जैसे कि अब की बार भाजपा सरकार में पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार के साथ देखने को मिल रहा है.

दरअसल भाजपा सरकार ने नवा रायपुर के चौक-चौराहों के नामकरण के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति की ओर सुझाए गए नामों पर सरकार चौक-चौराहों का नामकरण करेगी. लेकिन इसे लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया गया है कि पुरखों के नामों के साथ खिलवाड़ न किया जाए. भाजपा की सरकार नामकरण की राजनीति न करें.

इस मामले में आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पीकर हाउस में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में साहित्यकारों, इतिहासकारों और संस्कृतिकर्मियों के बीच कहा कि भाजपा नाम बदलने पर नहीं, काम करने पर विश्वास करती है. सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी सुनियोजित सिटी बनाने काम डॉ. रमन सिंह की सरकार शुरू हुआ था. अब राज्य में फिर से भाजपा की सरकार है तो नवा रायपुर के विकास को लेकर फिर से तेजी से काम शुरु हो गया है, जो कि पिछली सरकार में नहीं हो सका था.

विपक्ष को लग रहा है कि नवा रायपुर के नामकरण को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं विकास करने पर विश्वास रखते हैं. पिछली सरकार में जिन चौक-चौराहों का नाम जो रखना था रखा गया होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा और न ही उसे लेकर हमारी आपत्ति है, जो नाम किए सो किए. लेकिन अब आगे काम हमारा है. नवा रायपुर में अभी बहुत काम बाकी है, और जो काम बाकी है उसे हमारी सरकार अवश्य पूरा करेगी.

हमारी सरकार लक्ष्य और विजन के साथ काम कर रही है. सरकार की कार्ययोजना में है कि छत्तीसगढ़ के अंदर नवा रायपुर की तरह ही 10 और व्यवस्थित शहर बनाएंगे. पुरखों मान बढाएंगे. छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास बताएंगे. स्मृतियों को सहेंजेगे. धरोहरों को बचाएंगे. राजनीति नहीं करेंगे. विकास किया है, करते रहेंगे और आगे भी करके दिखाएंगे. और इसमें आप सबकी भागीदारी होगी. साहित्यकारों, इतिहासकारों, संस्कृतिकर्मियों, रंगकर्मियों, सबकी.

जन्माष्टमी शोभायात्रा पर मंत्री देवांगन ने बरसाए फूल, भगवान श्रीकृष्ण को पालने पर झुलाया

रायपुर। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कोरबा शहर के विभिन्न मंदिरों में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव मे शामिल हुए। पुरानीबस्ती कोरबा स्थित रानी रोड दुर्गा मन्दिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर स्थानीय वार्ड वासियों द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई, इस शोभायात्रा में मंत्री श्री देवांगन शामिल हुए। मंत्री श्री देवांगन ने श्री कृष्ण की आरती की। वार्ड वासियों के साथ मंत्री श्री देवांगन ने श्री कृष्ण झांकी पर फूलों की वर्षा की। मंत्री श्री देवांगन ने वार्ड वासियों और समिति को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि सनातन परंपरा में आस्था रखने वालों के लिए श्री कृष्णा प्रेरणा स्रोत हैं, गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है और सभी धर्म को साथ में लेकर कैसे चला जाता है इसे उन्होंने सिखाया भी है। आज हम सभी को श्री कृष्ण के बताएं मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल तिवारी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन, पार्षद धनश्री साहू, राकेश नागरमल, लक्ष्मण श्रीवास व समिति के विशाल साहू, अंशु तिवारी, जयंत श्रीवास, वीरेंद्र साहू, राहुल तंवर समेत अधिक संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे। तत्पश्चात् मंत्री श्री देवांगन सीतामणी स्थित श्री सप्तदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बनाए गए विभिन्न झांकियों के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन किए। कृष्ण भगवान की जीवंत मनमोहक झांकी देख मंत्री भाव विभोर हुए।

राजधानी में दो नए फैमिली कोर्ट का गठन, 2 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई

रायपुर। राजधानी में 2 सितंबर से दो नए फैमिली कोर्ट का गठन किया जा रहा है। विधि विधायी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें दो अतिरिक्त फैमिली कोर्ट के गठन और उनके लिए दो जजों का सेटअप भी तय कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के विधि विधायी विभाग के प्रिंसिपल सिक्रेटरी रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रायपुर में तृतीय और चतुर्थ अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की स्थापना की जा रही है। इन न्यायालयों में 2 सितंबर से पारिवारिक मामलों की सुनवाई शुरू होगी। इन कोर्ट्स में तलाक, ज्यूडिशल सिपरेशन, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी, और पति-पत्नी के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।

नए कोर्ट्स की स्थापना का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण निपटारा करना है। इन कोर्ट्स के जजों को पारिवारिक मामलों में समझौता करवाने और समाज के प्रति

प्रतिबद्धता का अनुभव होना चाहिए। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित इन न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य परिवार में उत्पन्न होने वाले विवादों को समझौते के माध्यम से निपटाना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाना है। जिन शहरों में फैमिली कोर्ट नहीं हैं, वहां इन मामलों को सिविल कोर्ट द्वारा सुना जाता है, लेकिन फैमिली कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया अलग और अधिक केंद्रित होती है। नए न्यायालयों के जजों को उनके कार्यक्षेत्र और अधिकार के बारे में भी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है। तृतीय और चतुर्थ अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, रायपुर के राजस्व जिले के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करेंगे, जिन्हें प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। इस कदम से रायपुर में पारिवारिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पुरुषोत्तम पांडेय, शरद चंद्र पवार गुट के प्रदेश संयोजक नियुक्त

रायपुर। एनसीपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम पांडेय को शरद चंद्र पवार गुट का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ति एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार झा ने की है। जारी नियुक्ति आदेश में राष्ट्रीय महासचिव झा ने लिखा है पुरुषोत्तम पांडेय को राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के निर्देश पर छत्तीसगढ़ का संयोजक नियुक्त किया जाता है उम्मीद हैं कि आप पार्टी के विकास के लिए बेहतर कार्य करेंगे इस नियुक्ति को लेकर प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम पांडेय ने बताया की 2003 से वे एनसीपी से जुड़े हैं वे प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं इसके साथ ही वे अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे लेकिन वे शरदचंद्र पवार जी के साथ काम करना चाहते थे इसलिए अध्यक्ष का पद छोड़ दिया अब उन्हें शरद पवार गुट से फिर से प्रदेश संयोजक की ज़िम्मेदारी दी गई है वे इस ज़िम्मेदारी का पूरी ताक़त के साथ निर्वहन करेंगे और प्रदेश में पार्टी को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. इस नियुक्ति के लिए वे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं पुरुषोत्तम पांडेय के नियुक्ति पर मनीष गट्टानी सोनू गोस्वामी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

अस्पताल के पांचवें मंजिल से गिरकर मरीज की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में स्थित मेडलाइफ अस्पताल के पांचवें मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक 60 साल के मरीज की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना रविवार देर शाम की है। तेलीबांधा पुलिस के मुताबिक मरीज ओडिशा के बरगढ़ जिले के ग्राम छिंदईकेला, बरपाली का रहने वाला था। मृतक राम बिस्वाल को उसके परिजन ओडिशा से मानसिक रोग का इलाज कराने 22 अगस्त को अस्पताल लेकर आए थे। जहां पांचवें मंजिल पर स्थित जनरल वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था। रविवार देर शाम को अचानक पांचवें मंजिल की खिड़की से संदिग्ध परिस्थिति में वह गिर गया। इस घटना से अस्पताल में अफरातफरी मच गई। खून से लथपथ मरीज को अंदर ले जाने पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मरीज ने खुदकुशी की है या कोई हादसा है, यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि उसे किसी ने वार्ड से नीचे कूदते हुए नहीं देखा। हालांकि पुलिस का कहना है कि मरीज ने बिना ग्रिल लगे खिड़की से नीचे कूदकर खुदकुशी की है।

भाजपा आंदोलनरत किसानों को अब बलात्कारी बता रही है

रायपुर। भाजपा सांसद कंगना रनौत के द्वारा किसानों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सांसद और नेता अपने बड़े केंद्रीय नेताओं के सह में लगातार किसान आंदोलन के खिलाफ अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर किसानों को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को पहले आतंकवादी नक्सली, राष्ट्रद्रोही, टुकड़े-टुकड़े गैंग बोलकर अपमानित किया था और अब भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में रेप और हत्या होने की बात कह कर किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बता रही। कंगना रनौत का यह बयान आरएसएस बीजेपी के द्वारा लिखी गई पटकथा का हिस्सा है। आरएसएस और भाजपा हमेशा आंदोलन करने वालों की छवि धूमिल करने इस प्रकार से साजिश और षड्यंत्र रचते हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान सबसे ज्यादा हताश और परेशान है। किसानों से जो वादा किया गया था 10 साल में मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। किसान आंदोलन के दौरान कमेटी बनाकर उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था.

वर्षावास के पावन अवसर पर धम्म देशना कार्यक्रम हुआ सफल संपन्न

रायपुर। डां,राजेन्द्र नगर बुध्द विहार रायपुर में भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई एवं पंचशील बौद्ध संघ रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में वर्षावास के पावन अवसर पर धम्मदेशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पांच भंते द्वारा धम्मदेशना दी गई जिसमें भंते सम्पजाणो असम से, भंते महानाम नागपुर से, भंते दीठ्ठिविशुध्दि बालाघाट से, भंते उत्तमों मग्गो बालाघाट से, भंते करूणा बोधि, सभी पांचों भंते जी द्वारा दी गई धम्म देशना का कार्यक्रम बेहद ही प्रशसनिय रहा, उपस्थित बौद्ध उपासक एवम उपासिकायें सभी ने मन चित्त की एकाग्रता को जाना, आनापानसति, विपशना, ध्यान साधना, प्रज्ञा शील करूणा, अत: दीप भव:, बौद्ध धर्म के धम्म की महत्त्व एवम, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, इन सभी बातों को बेहद ही आकर्षक रूप से उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षु संघ ने, अपने अनुभव ज्ञान को व्यक्त किया। और कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सफल रहा। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव विजय गजघाटे और करूणा ताई वासनिक ने किया.

मूणत ने स्कूलों का उन्नयन करने चलाया विशेष अभियान

रायपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन से संबंधित अपने कार्यों का विस्तृत ब्योरा जारी किया। उन्होंने कहा कि वह अपने इस कार्यकाल में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अपने पूर्व के कार्यकालों के दौरान भी मैंने युवाओं और शिक्षा से जुड़े जरूरी निर्माण कार्यों को मूर्त रूप दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे जिसका उदाहरण नालंदा परिसर समेत सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण और कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण है। इसी कड़ी में अब यह हम सब की जिम्मेदारी है कि नव निहालों को शिक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करें। मूणत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार बच्चों के मानसिक शारीरिक और शैक्षणिक विकास से जुड़े कई प्रयास कर रही है, मेरा भी यही प्रयास है। महज 8 महीने के कार्यकाल में कई विकासकार्यों को आगे बढ़ाया है। इसमें स्कूलों विशेष तौर पर स्कूलों के कायाकल्प का कार्य उल्लेखनीय हैं। मूणत ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2024 में महीने में रायपुर पश्चिम विधानसभा के हर स्कूल का जायजा लिया था.

मुख्यमंत्री से कुनकुरी विस के ग्रामीणों ने की मुलाकात

रायपुर। जशपुर जिले के ग्राम पंचायत तामासिंघा, बंदरचुआं और आश्रित ग्रामों के पंचों तथा ग्रामीणों के वार्षिक भ्रमण में अब एक नई जगह जुड़ गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया के आसपास के गांवों से वार्षिक भ्रमण पर राजधानी रायपुर पहुंचे ग्रामीणों ने गांव लौटने से पूर्व यात्रा के अंतिम पड़ाव में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपनी यात्रा के बारे में रोचक बातें साझा की। मुख्यमंत्री ने सभी का हालचाल जाना और बारिश, खेती-किसानी सहित गांव से जुड़ी ढेर सारी बातें की। इस मौके पर ग्राम तामासिंघा के सरपंच श्री संकेत साय पैंकरा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री साय सभी से बड़ी आत्मीयता से मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल अच्छी बारिश हुई है और पैदावार भी अच्छी होगी। श्री साय ने कहा कि

कुनकुरी और आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, इसके लिए सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आने वाले समय में सिंचाई के साथ अन्य समस्याएं भी दूर हो जाएगी।मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सामुदायिक भवन के स्वीकृति की जानकारी दी और बच्चों के खेलकूद के लिए जरूरी अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात कही। ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री के सामने आत्मीयता से अपनी बातें रखी। यात्रा के बारे में बताया, गांव के बारे में जानकारी दी और कुछ समस्याएं भी रखीं। ग्रामीण अपनी बात उनसे ऐसे साझा कर रहे थे, मानों गांव के अपने किसी साथी को बता रहे हों। ग्रामीणों ने बताया कि श्री साय शुरू से ही ऐसे है, वें कहीं भी रहें उनका अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों से हमेशा ऐसा ही लगाव रहा है। सांसद रहते हुए भी क्षेत्र के विकास के लिए जुटे रहे और उनका यह स्वभाव आज भी नहीं बदला है। हमने उनका संघर्ष देखा है और आज जब वो प्रदेश के मुखिया है, यह बात हमें गौरव से भर देती है।

गौरतलब है कि तामासिंघा और आसपास के ग्राम पंचायत के सभी पंच अपने परिजनों के साथ प्रतिवर्ष प्रदेश के विभिन्न इलाकों के भ्रमण पर निकलते है। इसी कड़ी में पंचों के प्रतिनिधिमंडल ने अपने परिजनों के साथ इस वर्ष मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, राजधानी रायपुर के मंत्रालय, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, जंगल सफारी, राम मंदिर और पुरखौती मुक्तांगन का भ्रमण किया। इस मौके पर श्री सायनंदन राम, श्रीमती सुचिता लकड़ा, सचिव श्री अनुराग तिवारी, श्रीमती लिवावती बाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित थे।

दादा गुरुदेव इक्तिसा जाप समापन में शताब्दी-ऐषणा ने जमाया गुरुभक्ति का रंग

रायपुर। आचार्य जिनमणिप्रभ सूरीश्वर द्वारा प्रतिष्ठित जिनकुशल सूरि जैन दादाबाड़ी, भैरव सोसायटी में 5 अगस्त से जारी 21 दिवसीय दादागुरुदेव इक्तिसा जाप के समापन समारोह दिवस पर देर रात तक शताब्दी ढ़ेलडिया व 5 वर्षीय बिटिया ऐषणा ने गुरुभक्ति का अनूठा रंग जमाया। माँ बेटी ने नवकार मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा , इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा के मंगलाचरण से भजन संध्या का आरम्भ किया। चलो रे मालपुराधाम दादा ने सबको बुलाया है। मालपुरा में ऐसा एक गुलाब है जो दुनिया में

ऐसा याराना । भक्ति की रात दादा आज थाने आणो है जैसे गुरुभक्ति के भजनों से भक्तों को सराबोर कर दिया। सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद महासचिव महेन्द्र कोचर , ट्रस्टी टीकम जैन , नीलेश गोलेछा व मुख्य अतिथि ऋषभदेव जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कांकरिया ने बम्फर ड्रा की विजेता रीतू डाकलिया, लक्ष्मी नगर पचपेड़ी नाका को सोने की चैन से पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मंजू कोठारी ने किया। बम्फर ड्रा सोने की चैन के लाभार्थी श्रीमती चन्दरी देवी कांकरिया परिवार सुमीत ग्रुप, प्रतिदिन के पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार के सुभाष चंद विजय कुमार पुगलिया , द्वितीय स्व तानिष गोलछा के आत्मश्रेयार्थ सुशीला देवी पदम् चंद गोलछा व तृतीय पुरस्कार अशोक चंद प्रशांत कोचर परिवारों की ओर से प्रदान किया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.